

Vol. I
No. 17



Wednesday
17th March, 1951

HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES Official Report

PART II—PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

CONTENTS

	PAGES
Business of the House	977
Resolution Re: Financial Aid to Handloom Weavers—Adopted as amended	978-987
L. A. Bill No. VI of 1951, the Hyderabad Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1954-1st reading negatived ..	987-1000
Resolution Re: Pakistan U.S. Military Pact—Discussion not concluded	1000-1087

THE HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY

Wednesday, the 17th March 1954

The House met at Half Past Two of the Clock

[MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

QUESTIONS AND ANSWERS

(See Part I)

BUSINESS OF THE HOUSE

شری کے - ایل - نرسمہا راؤ (یلندو - عام) - آج نان آفیشیل ڈے
(Non Official day) ہے تو ایسی صورت میں آفیشیل بل (Official Bill) کیسے
انٹرویوس (Introduce) کیا جا رہا ہے -

مسٹر ڈپٹی اسپیکر - انٹرویوس (Introduce) کرنے میں کوئی ہرج نہیں
ہے -

شری کے - ایل - نرسمہا راؤ - جب ایسا ہے تو آفیشیل (Official days)
میں نان آفیشیل ہل کیوں انٹرویوس نہیں کئے جاتے ؟

Mr. Deputy Speaker : There is a convention to the effect that on non-official days, official motions can also be moved. It does not take much of the time of the House.

Shri K. Ananth Reddy (Balkonda) : According to the rule, when one kind of business is to be taken up, the House cannot take up any other type of business.

Mr. Deputy Speaker : the convention is to allow such official motions.

Shri K. Ananth Reddy : Rules prohibit it.

Mr. Deputy Speaker : Not in this instance.

**L.A. BILL NO. IX OF 1954, THE HYDERABAD
NURSES, MIDWIVES AND HEALTH VISITORS
REGISTRATION AMENDING BILL 1954.**

The Minister for Public Health, Medical & Rural Reconstruction (Shri Mehdi Nawaz Jung) : I beg to introduce :

L. A. Bill No. IX of 1954, the Hyderabad Nurses Midwives and Health Visitors Registration (Amending) Bill 1954

Mr. Deputy Speaker : The Bill is introduced.

Resolution Re: Financial Aid to Handloom Weavers.

(Resolution) سترڈی اسپیکر۔ کیا بل پہلے لیا جائے گا زیر بحث ریزولوشن (Resolution)
کو پہلے لیا جائے ؟

श्री. व्ही. डी. देशपांडे (जिल्हागुडा) :—पहले रेजोल्यूशन लिया जाय तो बेहतर होगा।

वित्त तथा अद्योग मंत्री (श्री. वि. के. कोरटकर) :—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव बुनकरों के बारे में प्रस्तुत किया गया था, उसके संबंध में जो कुछ जवाब दिया जा सकता था, वह मैं बहुत कुछ दे चुका हूँ। अब सिर्फ उसके बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो सकती है अतनाही कहने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ।

जिस प्रस्ताव का पहला क्लोज यह है कि हर एक बुनकर को सौ सौ रुपये ग्रांट के तौर पर दिये जायें। जिस वक्त की हमारी आर्थिक स्थिति देखते हुये यह असंभव मालूम होता है। दूसरा क्लोज यह है कि हर प्राथमिक शाखाके मूल धन का चार गुना सेअर कैपिटल के तौरपर कर्ज दिया जाय। वह भी जिस वक्त की हालत में नामुमकिन है। तीसरा क्लोज यह है कि जो कुछ माल बुनकर तय्यार कर रहे हैं उसका ६० प्रतिशत गवर्नमेंट ले ले। यह एक नामुमकिन सी चीज है, क्योंकि आखिर यह साठ फीसद कपडा लेकर गवर्नमेंट उसका क्या करेगी ? वह कोअ्री बिजनेस (Business) तो शुरू नहीं कर सकती, कि उसको लेकर बेचा जाय। चौथा क्लोज यह है कि यार्न (Yarn) के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वह माफ किया जाय। जिस वक्त हैंडलूम (Handloom) के कपडे पर जो सेल्स टैक्स है वह तीब रूपसे घी बब की हद तक पहले से ही माफ है। यानी पहले से ही यह टैक्स जिस पर काफी कम हुआ है। पांचवा क्लोज यह है कि बुनकरों से जो मकानका टैक्स पेसोकी बाबत टैक्स वगैरा वगैरा जितने भी टैक्सेस लिये जाते हैं उनको भी माफ कर दिया जाय। यह जरूर गैरमामूली सी चीज हो जाती है। मेरा जहां तक ख्याल है कि हैदराबाद में बुनकरों से भी ज्यादा गरीब बहुत से लोग है। वे भी कहने लगेंगे कि हमको भी यह जुमला टैक्सेस माफ किये जायें। दूसरी चीज जिसमे यह है कि यह टैक्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेती है। स्टेट गवर्नमेंट को जिसका अस्तित्सार नहीं है कि जिन टैक्सेस को एकदम बंद कर दें, और यह भी नहीं हो सकता कि यह अस्तित्सार के साथ रखे जा सकें। कुछवां क्लोज यह है कि सूत (यार्न) की किमत्त एक तृतियांश

घटा दी जाय। आज तो सूत कातते हैं वे जिस तरह से चाहें बेच सकते हैं। गवर्नमेंट को अस्तित्वा नहीं है कि वह किसी से कह सके कि फलों चीज की किमत कम करो और दूसरों को बेचो। जिसके बाद अेडव्हायजरी कमेटी में टेकनिकल परसोनेल याने माहरेफन रखने के लिये कहा गया है। यह अेडव्हायजरी कमेटी सिर्फ स्किम्स वगैरा बनाने के लिये है, और टेकनिकल अेडवाइस सिर्फ गवर्नमेंट या आर्ट सेक्शन को दिया जाता है, न कि वीवर्स को या प्रायमरी सोसायटीज को दिया जा सकता है। जिसलिये अेडव्हायजरी बोर्डस् में टेकनिकल मेंबर रखने की जरूरत नहीं है। आठवां क्लाज यह है। कि टेकनिकल ट्रेनिंग का अिन्तजाम किया जाय। जिस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से आठ सेंटर्स में टेकनिकल ट्रेनिंग का अिन्तजाम किया जा रहा है, और उसको जहां तक हो सके और बढ़ाया जायगा। नौवें क्लाज में कहा गया है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो सेस फंड हमको मिल रहा है उसको जहां तक हो सके बढ़ाया जाय। जिसके लिये मैं पहले अेक वक्त सवाल के जवाब में कह चुका हूं कि खुद गवर्नमेंट जिसके लिये काफी कोशिश कर रही है, और कर चुकी है। मगर केंद्रीय सरकार ने अपना अेक खास फार्म्यूला बनाया है, और १९४३ और १९४५ के बीच में हर स्टेट में जो यार्न खर्च किया जाता था, उसके लिहाज से सबको यह सेसफंड दिया जाता है। और भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि जिसमें रहोबदल नहीं कर सकते। मैं ने उस वक्त हाउस के सामने यह भी रख दिया था कि हमको जितने डिसअेडव्हान्टेजेस है उससे ज्यादा दूसरे स्टेटों को हैं क्योंकि उनको यहां बुनकर और करघे (लूम) ज्यादा होते हुए भी उनको हम से कम सेस दिया जा रहा है। बहर-हाल अेक असुल अुन्होंने बना लिया है और उसी के तहत यह बंटवारा किया जा रहा है। उसमें ज्यादा रहोबदल करने की कोअी गुंजाइश जिस वक्त नजर नहीं आती।

(Mr. Speaker in the Chair)

जिसी तरह से जिस रेजोल्यूशन में जो अेक तरमीम पेश हुअी है उसमें भी करीब करीब अिन्हीं मांगों को कुछ फर्क करके रखा गया है। उसमें पहली मांग यह है कि जहां तक हो सके वीवर्स सोसायटीज को लोन (Loan) दिया जाय। जिसके बारे में मुझे अितना ही कहना है कि गवर्नमेंट ने इसी वक्त करीब १७ लाख रुपया सेंट्रल वीवर्स सोसायटी को अपनी गैरंटी पर, और रास्त लोन के तौर पर, दिया हुआ है। जिस तरमीम में दूसरा क्लाज यह है कि शेडयूल्ड बैंक्स और रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ लोन देने की कोशिश करे। जिसके बारे में अितना ही कहना है कि किसी भी सोसायटी को या आदमी को लोन दिया जाता है तो उनकी कॅपिसिटी देखकर दिया जाता है। और मैंने जैसा कि अभी कहा जिस वक्त १७ लाख के अपूर लोन अपनी गैरंटी पर रास्त गवर्नमेंट ने दिया है। जिससे ज्यादा अपनी गैरंटी पर और लोन दिया जा सकता है या नहीं, जिस पर गौर किया जायगा। गौर नहीं किया जायगा अैसी बात नहीं है। और जिसके पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेस फंड था उसमें दूसरी अेक स्कीम निकाली गअी है, उसके आने के बाद जिसमें कुछ और अिमदाद मिलेगी अैसी अुम्मीद है। जिसलिये जिस क्लाज के तहत आज कोअी कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है। तीसरे क्लाज में यह कहा गया है कि जहां तक हो सके गवर्नमेंट अपनी खरीद का खाता हंडलूम कपडे तक ही महदूद रखे। गवर्नमेंट ने इसके बारे में पहलेअी अेक रेजोल्यूशन कर लिया है, और अब तक दो बार हाउस के सामने मैं इसके बारे में कह चुका हूं। जिस साल से अपने-अपने सिलसिले में प्रोवीजन भी ज्यादा किया है, और गवर्नमेंट की जरूरियत के लिये सब से पहले खादी को प्रिफरन्स दिया जायगा। अगर खादी न मिल सके तो हंडलूम के कपडे को प्रिफरन्स

दया जायगा। और अगर दोनों में से कोअी कपडा मुहैया न हो सके, तो फिर मिल क्लाय लिया जायगा। जिसमें अेक और तरमीम की गयी है कि गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को यह सिफारिश करे कि वीवर्स का हाअुस टैक्स और प्रोफेशन टैक्स वगैरा माफ कर दिया जाय। बहरहाल मैंने पहले ही कहा कि यह अेक प्रिन्सिपल की मांग है। वह किसी तरह से अिक्वीटेबल बेसिस पर नहीं ठहर सकती। अेक तबके के लिये कहना कि अुनमे प्रोफेशन टैक्स न लो, ओर दूसरों से लेते जायेगे, तो यह गैरसही मालूम होता है। लेकिन अगर हाअुस जिस तरमीम को पाम करता है तो अुमको लोकल सेल्फ गवर्नमेंटस् की तरफ भेज दिया जा सकता है। अिममे ज्यादा में कुछ आइवासन नहीं दे सकता। यार्न सप्लाय के बारे में यह कहा गया है कि वह सस्ता दिया जाय। मैंने पहले ही यह कहा था कि ये जो कन्सर्न्स है अुनका आपसी संबंध है। और जहां तक हो सके गवर्नमेंट अुममें जब तक कोअी खास वजह पैदा न हो जाय अुस वक्त तक जानबूझकर दस्तदाजी नहीं कर सकती। जिस तरमीम के क्लाय सात में कहा गया है कि टेकनिकल परसोनेल अेडव्हायजरी कमेटी में शरीक किये जायें। मेरा कहना है कि अगर अैसी ही मांग हो तो अेडव्हायजरी कमेटी में किसी टेकनिकल आदमी को रखना गवर्नमेंट कबाहत नहीं समझती। लेकिन कहना अितना ही है कि अेडव्हायजरी बोर्ड में, जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी टेकनिकल अेडव्हायस की जरूरत नहीं होती। अेडव्हायजरी बोर्ड को कौनमी स्कीम में कितने फंड डालने चाहिये अितना ही देखना पडता है। टेकनिकल अेडव्हायजर्स की जहां जरूरत है, अुन आठ सेंटरों में वह हैं। वहां वे रखे गये हैं, और अुनसे अिमदाद ली जा सकती है। अिमके बाद आठवें क्लाय में यह है कि ट्रेनिंग के लिये अिन्तजाम किया जाय। अिसके बारे में मैंने कहा कि जितना अिन्तजाम हो सकता है अुतना किया गया है। नौवे क्लाय में यह है कि गवर्नमेंट ऑफ अिडिया के सेसफंड में से जो कुछ ज्यादा हिस्सा मिल सकता है, अुसके लिये कोशिश की जाय। मैंने बताया कि कोशिश की गयी है लेकिन अब तक अुन्होंने नहीं माना है। लेकिन कोशिश बराबर जारी रहेगी। दसवीं मांग अिसमें बढाअी गयी है। अिसके बारे में मुझे शुब्हा है कि यह तरमीम के तौर पर यहां कैसे आ सकती है। क्योंकि असली रेजोल्यूशन में यह मांग नहीं थी। अिसलिये अुसको अमेंड करने का यह तरीका नहीं हो सकता। लेकिन यह मसला वीवर्स कॉन्फरन्स की तरफ से पहले कोअंपरेटिव डिपार्टमेंट के पास गया हुआ है, और अुस पर गौर हो रहा है। अिन चंद चीजों को कहने के बाद मैं अैवान की तबज्जे और अेक चीज की तरफ ले जाना चाहता हूं कि सेसफंड के जरिये से बुनकरों को बहुत काफी मदद जिस वक्त दी जा रही है। साढे बारा लाख रुपये के करीब जुदा जुदा स्कीम्स में ये खर्च किये जा रहे हैं। यह मदद १९५३-५४ में दी गयी है, और अुसी तरह से सेसफंड से अिस साल भी मदद अुनको मिलेगी। यह जो मदद अुनको मिल रही है अुसको देखते हुअे और कोअी खास ज्यादा लोन या ग्रांट वगैरा की जरूरत पडेगी अैसा मैं नहीं समझता। यह मदद किस तरह से दी गयी है अुसका ब्यौरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रोडक्शन-कम-सेल्स अेकटीविटीज के लिये ६ लाख ५० हजार, मार्केटिंग स्कीम्स के लिये ९१ हजार, लूम्स को बदलने के लिये १ लाख २५ हजार, मोबाजिल व्हेन्स के लिये ५२ हजार, पब्लिसिटी के लिये १० हजार, अिस तरह से दिये गये हैं। अितना देने के बाद कपडे के दामों को घटाने के लिये सबसिडी के तौर पर ३ लाख रुपये और दिये गये हैं। अिस तरह से जुमला साढेबारा लाख होते हैं। अिसी तरह से १२ लाख २८ हजार रुपये अिन स्कीमों के लिये अिस साल के लिये मंजूर हो चुके हैं। और अगले साल भी अिसी तरह की अिमदाद दी जाने की पूरी पूरी अुम्मीद है। गवर्नमेंट का जो बूष्टिकोष था वह मैंने हाअुस के सामने रख दिया है।

శ్రీ పెండె వాసుదేవ్—(గజ్వేల్) :

అధ్యక్ష మహాశయా,

నేను ఈ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు, ప్రభుత్వం కొంతవరకైనా చేసేత పాఠశాలమి కుల యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ముందుకు వస్తుందని కొండంత ఆశతో ఈ తీర్మానం తీసుకు వచ్చాను. చివరికి 'డబ్బులేదనే' పాత పాటనే ఆర్థికశాఖా మంత్రిగారు పాడారు ఈమోస్తరు ప్రభుత్వ ధోరణి చాలా విచారాన్ని కలిగిస్తోంది. ఈ రోజున కరువు కాటకాల లో పాఠశాలమి కులు చిక్కకొని నానా యిక్కట్లు పడుచున్నారు. తోటి రాష్ట్రాలలోని ప్రభుత్వ ఆదరణ చూస్తున్నాం. చేసేత పాఠశాలమి కులను అన్ని విధాలా రక్షించడానికి వారివద్దనుంచి వృత్తిపన్ను, ఇంటిపన్ను తీసుకొనకుండా వుండడానికి నూతనంగా ఏర్పడ్డ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిశ్చయించింది. ఆ సంగతులన్నీ మన ఆర్థిక మంత్రిగారికి విన్నవించినప్పటికీ ఇక్కడ సాధ్యపడదని నెలవిచ్చారు. అయితే నేను ప్రవేశ పెట్టిన తీర్మానంలోని ఒక్కొక్క కోర్కెను తీసుకొని, వాటిని ఎందుకు ప్రవేశపెట్టానో ఎక్కడైనా తైము తీసుకొనకుండా చెబు తాను. చేసేత పాఠశాలమి కులకు ప్రతి ఒక్కరికీ నూరు రూపాయలు చొప్పున వడ్డీలేకుండా దీర్ఘకాల వాయిదాలమీద అప్పు యివ్వాలని కోరాను. దీనికి సవరణగా, ఆ నూరురూపాయల అప్పు పాఠశాలమి కునికి కాకుండా ప్రాథమిక సంఘాలలో పాఠశాలమి కునిపేరే వాటాధనంగా జమకట్టించాలని సవరణ వచ్చింది. ఈ నాడు మన సంస్థానంలో వున్న ప్రాథమిక సంఘాలు పూర్తి అధ్వాన్న పరిస్థితిలోకి రావడం జరిగింది. దానికి రెండు కారణాలున్నాయి. ఒకటి ఈనాటి ఆర్థిక సంక్షోభం అది ప్రధానమైన కారణం. రెండవది, ఆ ప్రాథమిక సంఘాలు స్వార్థపరుల చేతుల్లో యిరుక్కుపోయాయి. ఈ నాడు ప్రాథమిక సంఘాల్లో పాఠశాలమి కునకు తన వాటాధనం రూ. 30 లు తన కళ్ళకు కనపడకుండా హరించుపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ పరిస్థితుల్లో పాఠశాలమి కునికి అప్పుగా యివ్వాలన్న నూరు రూపాయలు, వాటాధనం క్రింద ప్రాథమిక సంఘాల్లో జమకట్టడంవలన, దానిని స్వార్థపరులు దిగమిరిగి చివరకు పాఠశాలమి కునికి ఏమాత్రం లాభం కలగకుండా పోతుంది. కాబట్టి ఆ సవరణను పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాను. ఆ నూరు రూపాయలు పాఠశాలమి కునికి అప్పుగా యిచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తే ఏదోవిధంగా పాఠశాలమి కుడు గిట్టుబాటుగాకపోయినా ఎక్కువధరైనా పెట్టి నూలునుకొని గుడ్డ తయారు చేసి అంగట్లో అమ్ముకొని కొంతవరకైనా యీ కరువు నుంచి బయటపడేందుకు అతనికి అవకాశం వుంటుంది. పాఠశాలమి కుని చేతులో డబ్బు పడితే, దానిని చెడగొట్టుకునే ప్రమాదం వుందని అంటున్నారు. ప్రభుత్వంవద్దనుంచి పూచీపడి తీసుకొన్న డబ్బును చేసేత పాఠశాలమి కుడు దిగమిరిగేస్తాడని మనం భయపడవలసిన పనిలేదు. కాబట్టి ఆ సవరణ తెచ్చిన వానిని ప్రార్థిస్తున్నాను. మనం అందరం కలసి ఏకాభిప్రాయంతో మంత్రిగారిపై వత్తిడి తీసుకువచ్చి, పాఠశాలమి కునికో ఆ నూరు రూపాయలు, వడ్డీలేకుండా దీర్ఘవాయిదాలమీద తీర్పు కునే పద్ధతిని అప్పు యిప్పించేందుకు ప్రయత్నించాలని, ఆ సవరణను డేవ సంహరించుకోవాలని, కోరుతున్నాను.

నాకు తెచ్చిన రెండవ సవరణలో ఏవర్యు కోఆపరేటివ్ సొసైటీలకు ప్రభుత్వం అప్పులు ఇప్పించాలని కోరారు. అసలు ప్రజల సమస్యలు ప్రభుత్వం తీర్చవలసిన అవసరం కలిగినప్పుడూ

డబ్బులేదని చెప్పి తప్పించుకోవడం ఈ ప్రభుత్వానికి అలవాటైపోయింది. కాబట్టి ప్రాథమిక సంఘాలకు అప్పులిప్పించేందుకు యీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందా? ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక అను దృష్టిలో పెట్టుకొని, ప్రాథమిక సంఘాలకు కూడా అప్పులు యిప్పించేందుకు యీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయాలని కోరుతున్నాను. కేంద్ర సంఘానికి ౧౩ లక్షల ౫౦ వేలు అప్పు యిచ్చామని చెప్పారు. నిజమే. ఆ డబ్బు కేవలం కేంద్ర సంఘానికి అప్పుగా యిచ్చినంత మాత్రాన ౧౮౦ ప్రాథమిక సంఘాలయొక్క ౧ లక్ష ౩౦వేల పారిశ్రామిక కల యొక్క సమస్య పరిష్కారం అయిందని అనుకోవడం సరైనదే కాదు. ఈ ప్రాథమిక సంఘాల్లో డబ్బులేకుండా మూలధనానికి ముప్పు వాటిల్లే పరిస్థితి దాపురించింది. కాబట్టి ప్రాథమిక సంఘాలకు డబ్బు అప్పు యిప్పించాలని కోరుతూ, నా తీర్మానంలో ఏదైతే రెండవ కోరిక వున్నదో దానిని అంగీకరించాలని కోరుతున్నాను. దీనికి తోబడిన సవరణ, పోటీగా తొచ్చారని అననుగాని, పేరే స్వరూపంలో తోబడిన సవరణను ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతున్నాను.

నా తీర్మానంలో మూడవ కోరికలో ప్రభుత్వానికి అవసరమయ్యే గుడ్డలో సగభాగం చేసేత గుడ్డను కొనాలని పెట్టాను. మద్రాసు, ఆంధ్ర రాష్ట్రాలలో కూడా ఈ విషయాన్ని దాదాపు అక్కడ ప్రభుత్వాలు అంగీకరించి అమలులో పెడుతున్నాయి. కాబట్టి నేను కోరేది ప్రభుత్వావసరాలకు కావలసిన గుడ్డలో సగభాగం చేసేత గుడ్డను కొని వాడాలని కోరుతున్నాను. నేను ఊరిగారితో మాట్లాడినప్పుడు, చుప్పానీల డ్రోస్సుకు, రుమాళ్లకు దానికి, కొంత గుడ్డ అవసరమవుతుంది, దానికి చేసేత గుడ్డను కొనాలని కోరాను. ప్రభుత్వానికి కావలసినటువంటి రకాలచేసేత వారు తయారు చేయజాలరనే దీగులు, సంశయంపెట్టు కోసవసరం లేదు. ఏరకం గుడ్డ నయినా, మీ ముఖం కూడా కనవడే గుడ్డను, తయారు చేసే నిపుణత్వం, నేర్పరితనంగల సేతవారు న్నారు కాబట్టి ఎటువంటి గుడ్డ కావాలో అటువంటి డిజైను ప్రైమరీ సొసైటీల (Primary Societies) కిచ్చి సేయించుకొని, ప్రభుత్వావసరాలలో సగభాగం సేతగుడ్డ కొని తీర్పు కోసేందుకు ప్రయత్నం చేయాలని మనవి చేస్తున్నాను. చేసేత పారిశ్రామిక కలు మిలిటరీ డ్రోప్ ను తయారు చేస్తారా? పోలీసు డ్రోప్ ను తయారు చేయగలరా అని అనుమానంపెట్టు కోకండి. ఎటువంటి రకం గుడ్డనయినా తయారు చేసే యివ్వగల నేర్పరితనం చేసేత పారి శ్రామిక కలకున్నది. ముఖ్యంగా యిటువంటి జాతీయ పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించి ప్రభుత్వావస రాలను తీర్పుకొనవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద వున్నది. కాబట్టి ప్రభుత్వానికి కావలసిన గుడ్డలో కనీసం సగభాగమైనా సేత గుడ్డనుకొని వాడాలని కోరుతున్నాను. దీనికి కూడా ఒక సవరణ వచ్చింది. ఆ సవరణ తెచ్చినవారుకూడా సేత గుడ్డను ప్రభుత్వంవారు కొనాలని అంగీకరించారు. నేనుకోరినది సగభాగం కొనాలని, కాని వారు తెచ్చిన సవరణలో పూర్తిగా చేసేత గుడ్డను, అలిండియా ఖాదీ సంఘం సర్టిఫై చేసిన గుడ్డను కొనాలన్నారు. ప్రభుత్వానికి కావలసిన గుడ్డసంతా చేసేత గుడ్డనే కొనాలని కోరడం నాకూ సంతోషమే. కాని వారి సవరణలో యింకొక విషయమేమంటే అలిండియా ఖాదీ సంఘం సర్టిఫై (Certify) చేసిన గుడ్డను కొనాలన్నారు. అటువంటి సర్టిఫైడ్ గుడ్డనూ, సహకార సంఘాలద్వారా తయారయిన చేసేత గుడ్డనూ ప్రభుత్వావసరాలకు పూర్తిగా కొనాలని సవరణ పెట్టారు. కాని అటువంటి సవరణ సహకార సంఘాలలో పారిశ్రామిక కలు పెలవం కూడా

వున్నారు. చేనేత పార్శ్వామికులందరూ సహకార సంఘాలలో లేరు. వారందరినీ సంఘానికి వరచి సహకార సంఘాలలోకి తీసుకురావలసినదే. కాని మన పైనకూడా కొంత కర్తవ్యమున్నది. మన ప్రభుత్వం పైన, మన కార్యకలాపాల పైన ఎంతో మంది వెలుపల వున్న పార్శ్వామికులు అనుమానం పడుతున్నారు. వారికి ఆ విధంగా అనుమానం లేకుండా చేయాలంటే వారికి అన్నివిధాలా తోడ్పడే విషయంలో మనం కృషి చేస్తున్నామని వారికి నమ్మకం కలగాలంటే మన విధానాల్లో, ప్రవర్తనలో మార్పు రావాలి. ఈనాడు సహకార సంఘాలలో నున్న విధానాలు, అక్కడే పద్ధతులు చాలా అవకతవకగా వుండుటవలన పార్శ్వామికులకు సహకార సంఘాలు ద్వేష్యులై గంత కట్టుకొన్నట్లు కనబడుతున్నాయి. ఈ సహకార సంఘాలు వచ్చిననాటినుండి పార్శ్వామికులకు రవ్వంతైనా తాధం కలిగించే పరిస్థితులు ఏర్పడలేదు. పార్శ్వామికుడు సహకార సంఘాన్ని అదే 'నాది' అని అనుకొనేందుకు మీలు లేకుండా, స్వార్థపరులు చేరి ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది. కాబట్టి వీటిల్లో ఎంతోమార్పు రావలసివుంది. కేవలం సహకార సంఘాలలో తయారయిన గుడ్డనే ప్రభుత్వం కొనాలనే నిర్బంధం పెట్టవద్దు. పార్శ్వామికుల నందరినీ క్రమేపి సహకార సంఘాల్లోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సహకార సంఘాల్లో చేరనంత మాత్రాన్ని మీగుడ్డ కొనం అని అనడం సబబు కాదు. ఈ విధంగా నిర్బంధం పెట్టడం సరైనది కాదు. కాబట్టి ఆ సవరణ ఉపసంహరించుకోవాలని సవరణ తెచ్చినవారిని కోరుతున్నాను.

తరువాత నేల్సుటాక్సు మినహాయింపు విషయంలో మొన్ననే మార్చి ౬వ తేదీన పార్లమెంటు లో ఒక ప్రశ్న పేసినప్పుడు కేంద్ర పరిశ్రమల మంత్రి కృష్ణమాచారిగారు అంగీకరించారు. నేల్సుటాక్సునుంచి చేనేత గుడ్డను మినహాయించ వలసినదీగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సలహా తీస్తున్నామన్నారు. తరువాత నూలుగుడ్డపైన, నూలుపైన నేల్సు టాక్సు రద్దుకాకుండా వున్న రాష్ట్రాలవేర్కొని కృష్ణమాచారిగారు ఆ ప్రశ్నకు జవాబులో చదివారు. ఆ తీర్పులో హైదరాబాదు పేరు లేదు. అనగా హైదరాబాదులో నేల్సు టాక్సు నేత గుడ్డపైన రద్దు చేశారని ఆ జవాబు వలన అర్థమౌతోంది. ఇక్కడ నూరు రూపాయలపైనుండే అమ్మకాలకు తీసుకుంటున్నా మంటున్నారు. నేల్సు టాక్సు పూర్తిగా నూలుపై నుండే, నేతగుడ్డపై నుండే రద్దు చేసేందుకు ఆంధ్రరాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించినట్లు పత్రికల్లో వార్త వచ్చింది. మన ప్రభుత్వం ఆ ఒక్క కోరికపైనా అంగీకరించేటట్లు కనపడదు. కాని హైదరాబాదు సంస్థానంలో వున్నటువంటి ప్రజానీకాన్ని అణగారొక్కేందుకు వారిపైన ఎక్కువ పన్నులు పేసి ఖజానా నింపి ఉన్నతాధికారులను పోషించేందుకు మాత్రం ఈ ప్రభుత్వం హైదరాబాదు వెలుపలనున్న అన్ని రాష్ట్రాలలోని అధిష్టాన్ని పరిస్థితిని పెదకి పెదకి యిక్కడెక్కడో ప్రయత్నం చేయడం అలవాటైపోయింది. వెలుపల రాష్ట్రాలలో ప్రజలయొక్క అవసరాలు తీర్చేందుకు ఎటువంటి అభివృద్ధికర చర్యలు ఏ ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్నాయో వాటిని మాత్రం గ్రహించి తీసుకొనేందుకు ఈ ప్రభుత్వానికి అలవాటు లేకుండా పోయింది. ప్రజలనున్న ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా చేనేత పార్శ్వామికులను ఇంటి పన్నునుండే, వృత్తి పన్నునుంచి మినహాయించింది. ఆ ప్రకారం మన ప్రభుత్వంకూడా చేనేత పార్శ్వామికులకు ఇంటి పన్ను వృత్తి పన్ను మిన

హాయింఛాలని కోరుతున్నాను. అంతేగాక ఆంధ్రరాష్ట్ర ప్రభుత్వం అటు లక్షల రూపాయల చేనేత గుడ్డును కొనేందుకు అంగీకరించారు. అక్కడ కోటి రూపాయల చేనేత గుడ్డు మిగిలి పోయివున్నది. చేనేత కాంగ్రెసు అద్యక్షులు ప్రగడ కోటయ్యగారి కోర్కెప్రకారం, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఆ గుడ్డు క్రియ వికరీయాలకు సహాయం చేయాలని కోరితే అటు లక్షల సహాయం చేసింది. కాని ఈ ప్రభుత్వం మాత్రం, ఇక్కడ చేనేతగుడ్డు విడుదల కాకుండా పడిపోయివున్నప్పటికీ, ఎటువంటి సహాయం చేసేందుకు ప్రయత్నించడం లేదు. నేను ముఖ్యంగా కోరేది నేల్సు టాక్సునుంచి పూర్తిగా నేతగుడ్డును, నూలును మినహాయింఛాలని కోరుతున్నాను. సింగిల్ హాయింటుటాక్సు, నూరురూపాయలపైని అమ్మకాలకు రీసుకుంటున్నామంటే పరిహాస. పూర్తిగా నేతకు డెవలప్మెంట్ నూలు పైన, నేతగుడ్డుపైనా నేల్సుటాక్సు రద్దుచేయాలని కోరుతున్నాను. దీనికి ఒక సవరణ వచ్చింది. సహకార సంఘాలలో వుంటున్న వారు తయారు చేసిన గుడ్డుకు మాత్రం ఆ సంఘాలలోని నూలుకు మాత్రం నేల్సుటాక్సు (Sales Tax) రద్దు చేయాలని సవరణ తెచ్చారు. వెలుపలవున్న చేనేత పారిశ్రామికాల నందరినీ సహకార సంఘాలలోకి తోవాలనే సూత్రం నేనుకూడా పూర్తిగా అంగీకరిస్తాను. వాళ్ళ నందరూ సంఘటీతపరచి వాళ్ళ కోర్కెలను సాధించడానికి బలవత్తరమైన సంఘం ఏర్పాటు చేయవలసిందే. మనమందరం కలసి ప్రభుత్వంపైన ఎత్తిడి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నించవలసిందే కాని వెలుపలవున్న పారిశ్రామికాలను మనం నిర్బంధ పెట్టవద్దు. వారికి ముందరే బెదురుగా చెప్పవద్దు. మనం అవలంబించే విధానాలవలన సత్ప్రవర్తన వలన వారు సహకార సంఘాల లోకి రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వారు తెచ్చిన మొదటి నాలుగు సవరణలూ డెవలప్మెంట్ రీసుకోవాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. అయితే ఆ నాలుగు సవరణలలో వాళ్ళ వున్న సవరణల నన్నింటినీ అనగా ౫, ౬, ౭, ౮, ౯, ౧౦ సవరణలను నేను పూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నాను. ఆ నాలుగు సవరణలు మాత్రం నేను అంగీకరించలేదనే ధీగుబుపెట్టుకొని వేరే అభిప్రాయం కలిగించు కోవద్దని కోరుతున్నాను. వారి అయిదవ సవరణనుంచి కింద వరకు పూర్తిగా అంగీకరించాను కాబట్టి వారు పైవాటిని డెవలప్మెంట్ రీసుకొని తీర్చానాన్ని ఏకగ్రీవంగా సర్వసమ్మతంగా వుండే టట్లు అంగీకరించి సహకార సంఘాల వెలుపల వున్నవారికి కూడా సహాయంచేసేందుకు ప్రభుత్వం వారిని కోరుతున్నాను. ఇవ్వాలి ఏదో సమాధానం చెప్పి తప్పించుకొనేందుకు ప్రయత్నించడం మంచిదికాదు. పారిశ్రామికాలను అధ్యాప్త పరిస్థితులనుండి బయటకు తోవాలంటే వారికి ఆర్థిక సహాయం చేయడం అత్యవసరం. ప్రభుత్వం డబ్బులేదనే పాకుచెప్పి తప్పించుకోడానికి విద్వేదు. మేము ఇక్కడ అనేక సార్లు చెప్పాము. కోటానుకోట్లు వ్యయపరుస్తున్న అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోండి ; పైజాంకిచ్చే కొటిరూపాయలు ఒక సంవత్సరం ఆపండి, జాగ్రద్ధులకు జమిందార్లకిచ్చే నష్టపరిహారం అపి చేనేత పారిశ్రామికాలకు సహాయంచేసి ప్రస్తుత దుస్థితినుండి బయటకు తొడని, పదే పదే చెప్పాం. పైగా మురిగిగారేమి చెబుతున్నారంటే వారికిస్తే వీరికివ్వ వద్దా, వీరికిస్తే వారికివ్వవద్దా, ఈ చేనేత పారిశ్రామికాలకు సహాయంచేస్తే యింకాక పరిశ్రమ వారికి సహాయం చేయవద్దా? అని అంటున్నారు. అందరికీ సహాయం చేయవలసిందే. హైదరాబాదులో వున్నటువంటి ప్రజానీకంలో ఈ నాడు ఎవరూ నిరుద్యోగులుగా వుండవద్దు. రెండు వూటలో తిండి లేకుండా, కనీసం ఒకపూతైనా కడుపునిండా తిండి లభించేందుకు మనం ప్రయత్నించాలి. కోట్ల కొద్దీ ఖర్చు అవసరంగా మేముచెప్పవారి ఖర్చులు, తగ్గించండి.

నైజాంవద్దవున్న కోటాసుకోట్ల అప్ప తీసుకోండి. దానిని మన రాష్ట్రములోని పరిశ్రమలపై
ఖర్చు పెట్టండి. ఎప్పుడు చూసినా, డబ్బు లేదు, డబ్బులేదు, అనే దేవాళ్ళాకోరుతనం చూపెట్టడం
అలవాటై పోయింది. ఈ విధంగా చులకనగా తప్పించుకొనే పద్ధతి సరైనది కాదు. కాబట్టి
పారిశ్రామికలకు అన్ని విధాలా సహాయం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకురావాలని కోరుతున్నాను.
ఈ సవరణలలో ఒకటి మొదలు నాలుగువరకు ఉన్న సవరణలు ఉపసంహరించుకొని మిగతా సవరణల
లో ఈ తీర్మానాన్ని ఏకగ్రీవంగా అందరు గౌరవ సభ్యులూ అంగీకరించాలని కోరుతూ యింతటితో
నా ఉపన్యాసం ముగిస్తున్నాను.

Mr. Speaker : I shall first put the amendment of Shri
L. B. Konda to vote.

شری پنڈم واسدیو - امٹمنٹ کلاز بائی کلاز ووٹ پر رکھئے کیوں کہ
امٹمنٹس کو میں نے قبول کیا ہے -

Mr. Speaker : I shall put it to vote paragraph-by-para-
graph. The question is :

“For para 1 of the Resolution, substitute the following,
namely—

‘1. Financial aid in the form of loans be granted to
member weavers of Weavers’ Co-operative for increasing
their share capital to promote production activities;”

The motion was adopted.

Mr. Speaker : The question is :

“For para 2 of the Resolution, substitute the following,
namely—

‘2. The Government should arrange for loans to the
Weavers’ Co-operatives—

(i) by giving guarantees to Scheduled Banks ;
(ii) from Reserve Bank
for yarn dealings and marketing of handloom products ;”

The motion was adopted.

Mr. Speaker : The question is :

“For para 3 of the resolution, substitute the following
namely—

'3. The Government should purchase handloom products from Weavers' Co-operatives and Khadi from certified producing concerns only to meet all its requiries ;' "

The motion was adopted.

Mr. Speaker : The question is :

"For para 4 of the resolution, substitute the following, namely—

'4. Yarn and handloom products handled by the Weavers' Co-operatives be exempted from Sales-tax and arrears be waived ;' "

The motion was adopted.

شری پنڈم واسدیو - ۵ سے لیکر ۱۰ تک امنڈمنٹس میں قبول کر لیا ہوں۔

Mr. Speaker : The remaining paragraphs of the amendment, viz—

"For paras 5 to 9 of the resolution, substitute the following :—

'5. The Government should advise the Local Self Government bodies to exempt the weavers from the imposition of taxes such as House Tax, Profession Tax, etc ;

6. The State Government should arrange yarn supplies to the Weavers' Co-operatives at concessional rates, from local mills as well as from the mills outside the State by approaching the Central Government ;

7. The present Advisory Committee may suitably be expanded by associating more technical personnel with it ;

8. Preference for training should be given in the Technical Training Centres of Commerce & Industries Department to the nominees of Weavers' Co-operatives as well as training in dyeing, bleaching and finishing be extended in the Centres ;

9. (a) The Central Government be requested to revise the formula applied in determining the quota of each State from the Cess Fund and allot full amount due to the Hyderabad State.

(b) Since Hyderabad is an undeveloped area in the Handloom Industry the Central Government be requested to allot amounts from the Special Reserve Cess Fund earmarked for backward areas ;

10. Audit fees payable by Weavers' Co-operatives be waived and the Weavers' Co-operatives be exempted from payment of Audit fees till the end of June 1957."

have been accepted by the Mover of the resolution himself as such they need not be put to vote.

The question is :

"That the resolution as amended be passed. "

The motion was adopted.

**L. A. Bill No. VI of 1954, the Hyderabad Shops and
Establishments (Amendment) Bill, 1954.**

Mr. Speaker: I would like to know whether the House would like to take up first the Hyderabad Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1954, introduced by Shri V. D. Deshpande or the next non-official resolution.

Shri V. D. Deshpande : I think we should take up the Bill first because we can finish it earlier and then we can take up, the other resolution.

The Minister for Public Works and Labour (Dr. G. S. Melkote) : I have no objection to the Bill being taken up first.

Shri V. D. Deshpande : I beg to move :

"That L.A. Bill No. VI of 1954, the Hyderabad Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1954, be read a first time."

Mr. Speaker : Motion moved.

*श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—अध्यक्ष माहोदय, यह जो अमंडमेंट बिल है उसके लिये लेबर मिनिस्टर का मुझे सब से पहले शुक्रिया अदा करना चाहिये, क्योंकि उन्होंने कम से कम फर्स्ट रीडिंग तक जिस बिल को हाउस के सामने आने के लिये मौका दिया है।

I think it will be convenient for the Minister to reply if I speak in English.

This Bill seeks to amend section 36 of the Shops & Establishments Act. I shall first place before the House the object with which the Shops & Establishments Act had been enacted. The workers in factories received protection under the Trade Union Act of 1926 under which they were allowed to organise themselves and certain facilities were given to them. But the employees in shops and establishments, cinemas and other places of employment did not come under the purview of the Factories Act and also had not got the benefit of the provisions of the Act of 1926. So, it was thought necessary that there should be some Act to regulate the conditions of the employees in Shops and other Establishments and with this view the Government of Hyderabad and other State Governments in India promoted legislation under the name of the Shops & Establishments Act. As the preamble of this Act states, it was thought expedient to provide for the regulation of conditions of work in shops, commercial establishments, restaurants, theatres and other Establishments. After seeing the working of this Act in the last two years, we are feeling that certain sections of this particular Act should be amended. I had brought up a Bill similar to the present one sometime back before the House, but unfortunately, the Members on the Treasury Benches at that time did not allow it to come even to the stage of first reading.

I should like to point out to the House that unless we are of the opinion that the objectives with which this legislation was enacted should be done away with, we should have absolutely no objection to remove certain lacuna in that particular legislation. The question is, do we want that certain facilities which were intended to be given under this particular Act should be available to the employees or not? Under the Act we have provided certain restrictions

regarding the hours of work, that no employee should be made to work for more than 8 hours. Similarly, certain provisions regarding holidays are there. 'Recently, *i. e.*, about an year or so back, this House had passed an amendment to section 36 of the Act whereby a gratuity has to be given to workers who are removed from service without sufficient cause and it should be our purpose and duty to remove any lacuna that may be found in the Act. The Amending Bill which I have moved for first reading in this House incorporates this view. In the course of our experience during the last year and a half in organizing the employees in hotels, we have found that there is no protection in any section of this Act against dismissal or discharge of the workers for reasons other than misconduct, and we find that invariably the employers are resorting to dismissal of the workers after paying some gratuity. I can point out three such cases—one in Hyderabad and two in Secunderabad—where active workers of the Hotel Workers Union were removed by the employers, just because they felt that their presence in the hotel would be detrimental to their interests and feared that if an organised union existed the employers might be compelled to enforce the conditions of work of 8 hours a day and would have to provide other facilities.

Therefore, under the plea that they did not require the services of a particular employee and without giving any reason for his removal, taking shelter under the particular section that if they paid gratuity of 15 days wages per year of service they could dispense with the services of an employee, these employers removed them from service. The instances which I refer to are the cases of the Modern Cafe, Secunderabad and another Cafe—probably City Cafe. I have brought these cases to the notice of the former Labour Minister and even to the present Labour Minister and also to the Deputy Labour Minister. I have pleaded with them that unless certain facilities are given to the workers to organise themselves and unless they are given some protection—there is no protection for them at present as the Trade Union Act of 1926 does not apply to them—it is practically impossible for the small employees to get themselves organised. Let me point out that whether it is in the Rural areas or in the urban areas, howsoever good a legislation may be, unless it is enforced by the organised section of the people, the benefit of

such legislation cannot be derived by the people. For example in the Tenancy Act we have various provisions against eviction, but it has been our experience throughout the Hyderabad State that where there is an organised Kisan Sabha (Peasants' organisation) there alone we have been able to enforce the provisions of the Tenancy Act. Similarly, unless there is an organised union of workers, it is not possible to see that the provisions of various sections of the Shops & Establishments Act are enforced and see that the workers get the privileges or the facilities provided for under the particular legislation. In Nanded, when I was trying to organise hotel workers along with the peasants and other workers, it had been my experience that the managements and employers had various means at their disposal to thwart all my efforts to organise them. They could just pay 15 days wages as gratuity and say they did not want the services of a particular employee any more. I went to the Proprietor of a particular Hotel and asked him whether he was going to retrench the workers or whether he was going to close down the establishment. He was going to do neither; and he employed certain other people next day. The trade was flourishing, but still the active Union workers were removed. From this particular experience, it is evident that unless we provide in this legislation certain safeguards against these unwarranted removal of the employees, it will not be possible to implement the Act and afford the facilities provided for under its provisions. I am, therefore, pleading in this House that this particular Section 36 should be amended.

The other day, one of the dignatories of this House complained to me saying: "Well, an employee may come and slap me on my cheek; you may perhaps like me to go to Court and plead there! Do you want to help an employee in this way and encourage such behaviour?" My reply to him was, and in this House is, that if a particular employee misbehaves, then there are provisions in the Act which go under the name of 'misconduct' whereby certain action can be taken. If we amend the particular section in the way I desire it, it does not mean that the employee will be encouraged to misbehave as such, because there is already provision in the Act to safeguard the employer against it. It is in the interest of the employee that this particular section should be amended, but at the same time it does not go against the interests of the employer as such.

The amended section 36 of the Act seeks to provide that no employee should be removed or no employer shall dispense with the services of an employee except for a misconduct supported by satisfactory evidence recorded at an enquiry held for the purpose. An employee can be removed for misconduct, but what is the safeguard for the employee against the misuse of this provision; the only thing is that there should be satisfactory evidence to this effect. There should be a regular enquiry and the whole proceedings should be recorded. What I am suggesting is not something new. For example, in Nanded, where I had occasion to be the President of the Union—and I still continue as such—in all cases of misconduct, the worker concerned is called by the management, evidence is taken and recorded, and only after that the services of the employee are dispensed with. What I am asking for is not something which is not provided for the factory workers and I only want that the same benefits should be provided for the employees of the Shops and Establishments. That is why I want section 36 of the Act to be amended thus :—

“No employer shall dispense with the services of an employee except for a misconduct supported by satisfactory evidence, recorded at an enquiry held for the purpose.....” and secondly,

“.....or, without a reasonable cause, and without giving such person one month's notice or wages in lieu of such notice and without giving such a person a gratuity amounting to 15 days' average wages for each year of continuous service, subject to a maximum of average wages of 15 months”.

The reason for the removal of the employee should be reasonable. As the Act stands at present, we find that without giving any reason whatsoever an employee can be removed. As I have explained earlier, if there is no necessity for the employer to give any reason, then the active workers of the Union can be removed without any difficulty and in this way victimisation can take place and all possibilities of an organised union in this particular sector will become practically impossible. Therefore, I have provided that without giving a reasonable cause no employee should be removed, and secondly there should be a notice of one month. It

is rather peculiar that in the Act, the section says that the employee shall not leave the service unless he gives one month's notice, and this very obligation is not cast on the employer; it is only the employee who is made to give one month's notice and not the employer. The present Bill seeks to make it compulsory on the part of both the employer and the employee to give one month's notice, whether the employer wants to dispense with the service of an employee or the employee wants to leave the service of an employer. Secondly, it should be proved that there is a reasonable cause for the employer to dispense with the service of an employee. Thirdly, if the employee has been in service for a long time, gratuity should be given to him at the rate of 15 days' wages for each year of service of the employee in that particular establishment. The last one is not a new provision; it has been already provided by the Government.

I know I may be replied to by the hon. Minister for Labour or the Deputy Minister that the Government themselves are going to bring this amendment—as has been the practice of Governments in other States, and probably the Government of Hyderabad will follow their footsteps. Such promises have been held out to us not in respect of one amending Bill, but at least half a dozen.

Dr. G. S. Melkote : Can the hon. Member mention any ?

Shri V. D. Deshpande : I can mention the Money-lenders Act, the Criminal Procedure Code and one or two more. I am not referring to the Labour Department, but to the Government as a whole. As in other cases, probably the reply may be given that the Government themselves are going to amend the Act in the way they feel proper. But I wish to point out to Government that justice delayed is justice denied. I must say that unless such protection is given to the employees, it is not possible to get over the intransigence of the employers. Not only is this affecting the employees, but it is affecting the law and order position also. The Home Minister, sitting here, himself will be glad, I am sure, to testify how the non-affording of this facility to employees has affected the law and order situation in the City. Yesterday, there was a lathi-charge on the workers of Modern Cafe. About 4 or 6 months back, a similar situation developed in the City Cafe.

These things are occurring in the City of Hyderabad. The cases have gone to the Industrial Court. When the situation is deteriorating, Government will not be losing anything by accepting the particular Bill which has been brought up before the House, except probably that they might feel that the credit should go to the Treasury Benches and not a Member of the Opposition. I can understand if the hon. Minister for Labour gives a categorical assurance that the Government will issue an ordinance in this respect or they would introduce a similar Bill within a week. But if it is going to be delayed for months together then I will plead with them that it does not matter if a particular amendment is accepted, even if it comes from the opposition.

Yesterday, I was glad to hear an appeal of the hon. Home Minister that our country is going through a crisis and it is necessary for all those who stand for democracy to come and rally together. To create a good situation in India, it is necessary that the working class which occupies a strategic position in the whole order of things should be satisfied and given due protection. I feel that though this particular Bill is coming on behalf of the Opposition the Government should have, in the circumstances, no objection to accept it. I may assure the hon. Members that if any changes or amendments are to be introduced after the first reading and they are proper, absolutely I will have no objection. Even if I should have any objection, the majority is on the other side and they can carry them through. My only appeal is justice should not be delayed because it might amount to justice denied. Lastly, I shall plead with the hon. Minister that I am not putting anything new. There is nothing new under the sun, as the saying goes. In this particular regard, I am just reproducing, probably with a little change here and there or a phrase here and a phrase there, the same provision in the Madras Act. To refresh the memory of this House, I will just read out the relevant section again, i.e., section 41 of the Madras Act.

“Notice of dismissal :—No employer shall dispense with the services of a person employed continuously for a period of not less than six months except for a reasonable cause and without giving such person at least one month's notice or wages in lieu of such notice, provided, however that such

notice shall not be necessary where the services of such person are dispensed with on the charge of misconduct, supported by satisfactory evidence, recorded at an enquiry held for the purpose."

So if anybody goes through this particular wording, he would find that I have more or less reproduced the same in my amendment. If a Government which is on a border of ours—probably it is not on the border, but one State removed—can enact such legislation, I fail to see any reason why our Government too should not accept it. The other two sub-sections of section 41 of the Madras Act read thus :

" 2. The person employed shall have a right to appeal to such authorities and within such time as may be prescribed either on the ground that there was no reasonable cause for dispensing with the services or on the ground that he had not been guilty of misconduct as held by the employer.

3. The decision of the appellate authority shall be final and binding on both the employer and the person employed."

As may be seen, the second sub-section was reproduced in verbatim in my amendment. The third sub-section also was physically taken and put in my particular amendment.

Having explained all these points I hope that I shall not have to hear that the hon. Member may kindly withdraw the Bill as the Government itself is thinking to introduce a similar legislation. Before concluding, I will just point out to the House that there have been some printing mistakes and some omissions. In the sub-section which I want to replace, these words have not been printed there :

"No employer shall dispense with the services of a person employed." These words are not there and they may kindly be added there. Further in sub-section (4), in line 4, for the word 'or', the word 'for' is printed. It may be accordingly corrected.

I hope that this amending Bill will receive the consideration of the hon. Minister concerned. I also appeal to the House to think over the whole matter, and allow the Bill to have a passage in the House.

* *Dr. G. S. Melkote*: Sir, I was extremely pleased to find a peculiarly good effect that the speech of the Home Minister had made on the Members of the Opposition, particularly the Leader of the Opposition himself.

At the outset, he said it was very good that the Treasury Benches permitted him to go through the first reading of the amendment Bill. I thank him for the good sentiments he had expressed. I should also say that to a certain extent he had anticipated possibly what I was going to say.

I wish to remind him a few factors based on actual facts. The situation as it obtains in Hyderabad is different from that obtaining in Madras; where the Madras Act which he has just now read out is administered. Here in Hyderabad, the worker is entitled to a gratuity of 15 days. This is not to be found in Madras. The Leader of the Opposition did not mention this. The other advantages to which he referred were: (1) an enquiry or to cause an enquiry to be made with regard to the dismissal of the employee, and (2) setting up a machinery for adjudication, and (3) to make it obligatory on the part of the employer to give a month's notice or wages in lieu thereof. These were the three things. These were particularly considered in the 1951 Act.

During his speech, the Leader of the Opposition has also mentioned that the Trade Union Act applied only to the factories and not to the Shops and Establishments. I would like to correct him there and tell him that the Trade Union Act applies to both the factories as well as shops and establishments. With regard to dismissals and discharges, even as the Madras Act stands, these are being referred for adjudication and as such, there is absolutely no difficulty. So the only two points that are left for consideration are: (1) month's notice or a month's pay in lieu thereof; This matter is engaging the active consideration of the Government. It is very easy for Members of the Opposition to say that if the Government accepts it and pass an ordinance within a week the members of the Opposition would have no objection to the same. When I was one of the Presidents of a Labour Union I had similar occasions to complain to the then Government. With regard to the Shops & Establishments Act, I had told that the Government should move very quickly. That

is why when the Leader of the Opposition brought this amendment I thought it should be gone through because I too experienced similar difficulties. But seated as I am on the Treasury Benches, I have got to consider various other aspects about which possibly he is not aware. He did not place.....

Shri V. D. Deshpande : The hon. Minister may explain those things.

Dr. G. S. Melkote : Yes, I am doing that. He is possibly not aware that in Madras when such an enactment was made these administrative provisions made there. The Madras Shops & Establishments Act of 1947 extended to the City of Madras, to the municipalities constituted under the Madras District Boards and Municipalities Act of 1920, and all the major Panchayats as classified by the Government. The administration of the Act is enforced by 199 whole-time Inspectors designated as Asst. Inspectors of Labour assisted by a lower division clerk and a peon for each Asst. Inspector. These Asst. Inspectors should work under the control of Gazetted Inspectors. That shows the amount of establishment that would be necessary; and if the Government has got to accept any legislation, it has got to consider the administrative aspect of enforcing such a legislation. That is one of our difficulties. The second is before the Government makes up its mind in favour of a Bill of this type, it has got to give sufficient latitude to the proprietors of hotels themselves to make representations to the Government. Such time has not been allowed to those people. Government certainly considers this amendment bill very sympathetically, but in order that the Government may consider setting up the necessary administrative machinery and the consequential financial and other implications as well as in view of the time-lag that would be necessary in order to enable the proprietors to place their point of view before the Government, we consider that this Bill as brought before the House should not be pressed for. That is my only objection. With the principle itself, I agree entirely. I myself and my colleague, the Deputy Labour Minister, have been thinking on these lines. What exact shape it would take I am not in a position to foresee at present; but we are certainly considering this amendment Bill and very shortly—we do not desire to take very long time as

we also experience such difficulty—we would like to bring before the House the necessary legislation. I therefore request the Leader of the Opposition to withdraw this Bill and help me to bring in a comprehensive legislation as early as possible.

**Shri V. D. Deshpande :* Sir, Whether I have misunderstood the hon. Minister or he has misunderstood me, the point is this : The workers are fighting not mainly for gratuity but mainly for security of service. He feels that if he should get 15 days' wages.....

Dr. G. S. Melkote : I accept all those conditions.

Shri V. D. Deshpande : But my point is this. I have come to know that the advice given by the Labour Department on this point has been.....

Dr. G. S. Melkote : Whatever that advice might be, I said that the matter would be sympathetically considered.

Shri V. D. Deshpande : Anyway, I will express my views before I express what I want to do in this particular regard. I want that the Madras Act should be amended to provide a gratuity there also ; but that should not become a plea for not providing security of service. I have great objection to the Labour Department. I will come to that when we deal with the demands relating to it. The Labour Department has been putting spokes to get this Act amended for the last one year. Previously also, the Minister for Labour, probably without giving any thought to this, refused to amend this Bill, when I had brought in the amending Bill. Today I have got evidence that it is the Labour Department that is coming in the way of putting this amendment through.

Dr. G.S. Melkote : I am sorry, the hon. Leader of the Opposition is entirely wrong.

Shri V. D. Deshpande : I may be corrected. My impression won't go. Today I have got evidence with me that the Inspector for Shops & Establishments in Secunderabad is

moving in the cars of employers, is attending the meetings of hotel owners, is advising them how to dispense with the services of the employees and is trying in every way to help the employers. It is on the advice and guidance of such employees that the hon. Minister is feeling that in Madras gratuity is not given while in Hyderabad something very big has been given to the workers. It is the security of service that the worker wants and not the gratuity. I do not say that the 15 days' gratuity should be removed. Regarding the establishment that may be necessary we on this Side will vote for such establishment if it is in the interests of the workers. When we criticise the Government expenditure it is in that particular aspect where it is not in the interests of the public but where certain machinery is necessary to give facilities to the workers, nobody from this side can have any objection. That should not come as a plea from the Government.

Dr. G. S. Melkote: That is not a plea. What I said is that the financial aspects have got to be considered. What type of officers are necessary, whether we are having such officers or whether they have got to be trained to suit this particular suit—these are the considerations for which the hon. Leader of the Opposition has to give us time.

Shri V.D. Deshpande: Today some workers of Modern Cafe, City Cafe, etc., are removed. They are being victimised. Even if they go to the Industrial Court, the most that they can get is some gratuity for the period of years they have worked. We want their reinstatement. How is the Labour Department going to help? The Industrial Tribunal could not help unless the Act is amended. It can be proved in an Industrial Court that the worker was removed by the employer illegally. But what is the relief? His relief is only gratuity, not reinstatement. Therefore, I say that if nothing is done by the Government immediately in this respect, this fight of the employees in the city of Hyderabad, Secunderabad and in the district places which is there since this Act has come into vogue will continue without any relief. I want in the circumstances a categorical reply from the hon. Minister for Labour that at least during the course of this Session this particular Bill would be amended and the Bill introduced in this House during this Session. I think it

should be possible. If the Government could have an ordinance exempting the Deputy Ministers for holding offices of profit overnight—or with a delay of one week,—then why is it not possible that during the course of this Session, say before 10th April such a small piece of legislation can be brought into this House, especially when there was a conference of Labour Officers recently, when specially this matter was discussed and when the hon. Minister for Labour was a Trade Union Worker for a long time and President of INTUC and when, as he himself said, he had experienced all these things. In these circumstances, I see no reason why a promise should not be forthcoming from him that during the course of this Session itself he will be in a position to amend this particular Act so as to remove the difficulties the workers are experiencing.

I see no reason why a promise that during the course of this Session he will be in a position to amend the Shops and Establishments Act should not be forthcoming from the Labour Minister. This would remove the difficulties which the workers are experiencing now. If an assurance is made that during the course of this Session say about 10th April, a legislation of this type will be introduced, I will have no hesitation to withdraw the bill I now propose. Let me state very clearly that the next Session of the House may be called only after six months and in the meanwhile the sufferings of the workers cannot be remedied and the struggle between the employers and employees would continue. In view of this, I will once again plead with the Minister that it should be possible for the Government to take this matter up within the course of this Session and I request him to give such an assurance. In that case I have no objection to withdraw it.

***Dr. G. S. Melkote :** There seems to be certain amount of misunderstandings in the mind of the Leader of the Opposition. He referred to the Madras Act, wherein a provision is made for adjudication. I said that the same type of adjudication is taking place in Hyderabad today and once it is there, it is for the Judge to declare whether the dismissal is legal or not. Once he says that it is legal naturally Government cannot interfere; if it is not legal, naturally the proprietor of the shop or establishment has to take the employee back. What other measures the Leader of the Opposition

1000 17th March, 1954.

*Resolution re : Pakistan-U.S.
Military Pact.*

envisages in the Act, is not clear. The provision is there, as it is.

With regard to his other point that I should categorically mention that I would bring such a legislation before the end of this Session, I will certainly not be able to do this.

The Government has its duty to perform to everyone and it will necessarily see that the conditions of the labour improve. I have seen their difficulties and know them. Such legislation should be brought about as early as possible. Even then, I have to give everybody a chance to represent their point of view. The time is too short and I will definitely not be able to come before the House with a legislation of the type needed. I said that Government is viewing the whole matter very sympathetically and a legislation of an almost similar type will be brought as early as possible.

Mr. Speaker : The Question is :

“That L.A. Bill No. VI of 1954, the Hyderabad Shops and Establishments (Amending) Bill 1953 be read a first time.”

The motion was negatived.

Resolution : Re : Pakistan—U. S. Military Pact.

Mr. Speaker : A resolution is to be moved by Shri V. D. Deshpande. He may move the resolution.

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव यू. एस.-पाक पॅक्ट के सिलसिले में हावुस के सामने मुद्दा करना चाहता हूँ। यह प्रस्ताव जब भेजा गया था उस वक्त के हालात और आज के हालात में तबदीलियाँ बाक्या होने की वजह से मैंने जिस रेजोल्यूशन में कुछ तबदीलियाँ की हैं। उन तबदीलियों के लिये अगर मुझे बिजाजत मिलें तो मैं जिसको जिस तरह मुद्दा करना चाहता हूँ।

मैसर्स اسپیکر - بات یہ ہے کہ یہ رزولوشن پہلے آیا تھا - اس میں آفس کی جانب سے کرکشنس کئے گئے تھے - اسے چھاپنے کے بعد آنریبل ممبرس کو ریزولوشن کی کاپیاں دی گئیں - پھر اس سے متعلق آنریبل ممبرس کی جانب سے ترمیمات پیش کی گئیں - آپ اصل رزولوشن میں جو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ ترمیمات پیش کرنے والے آنریبل

ممبرس کو اوس پر کچھ اعتراض ہو۔ میری رائے میں یہ امنڈمنٹس کچھ ایسے زیادہ اہم تو نہیں ہیں۔ لیکن ہر سکتا ہے کہ آنریبل ممبرس اس پر کچھ کہیں۔ اگر موجودہ پرنٹڈ ریزولوشن کو مڑو کیا جائے تو اس کے بعد معزز رکن امنڈمنٹ کے طور پر اس میں تبدیلی فرما سکتے ہیں۔ اورجنل پرنٹڈ ریزولیشن (original printed resolution) میں دس آنریبل ممبرس نے امنڈمنٹس پیش کئے ہیں۔ آپ پرنٹڈ ریزولیشن میں جو تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ان دس آنریبل ممبرس کو منظور ہیں؟

شری عبدالرحمن (ملک بیٹھ) - ہاں ہمیں منظور ہیں۔

Shri V. D. Deshpande : I beg to move :

“That this Assembly expresses grave concern at the pact of military alliance and aid between America and Pakistan by virtue of which the American armed forces are expected to build their war bases in Pakistan under the plea of strengthening them. This pact while endangering the freedom and independence of Pakistan, brings the danger of war on the border of India and attempts to coerce India into war camp. It will further involve the whole of South East Asia in the preparation for acts of aggression and brings near the out-break of Third World War.

This Assembly, while expressing solidarity and friendship between the people of India and Pakistan calls upon the Government of India to raise a powerful campaign against this pact and develop Indo-Pakistan friendship, As an solidarity and World Peace.

This Assembly pledges its full support to the Government of India in this respect.”

Mr. Speaker : Resolution moved.

Shri L. B. Konda (Asifabad-General) : I beg to move :

(1) That for para 1 substitute the following :

“This Assembly expresses its grave concern at the Military Aid Pact between the United States of America and Pakistan leading to consequences endangering the freedom

1002 17th March, 1954.

*Resolution re : Pakistan-U. S.
Military Pact.*

and peace of India including South-East Asia and even precipitation of third world war."

(ii) For para 2, substitute the following :—

"This Assembly recommends to the Government of India to take strong security measures to encounter the impending danger to freedom and peace of India ; and further recommends to launch effective campaign for Indo-Pakistan friendship, Asian solidarity and world peace."

(iii) In line (1) of para 3, omit the word "also."

Mr. Speaker : Amendment moved.

Shri Ankushrao Ghare (Partur) : I beg to move :

(i) That in line 12 of the Resolution, delete the following words, namely :—

"revere all connections with the United States of America"

(ii) Add the following at the end of the Resolution :

"and emphasises the need of extending compulsory military training to all students of high schools and colleges above the age of 18 years."

Shri V. B. Raju (Secunderabad-General) : The first portion of the amendment is not necessary, because it has been accepted by the mover himself in his own amendment.

Mr. Speaker : Part 2 of the amendment moved.

Shri V. D. Deshpande : The discussion may take place after interval. I do not want to be interrupted after two or three minutes by an interval.

Mr. Speaker : I expected the hon. Member would begin his speech immediately. All right we will adjourn, now.

The House then adjourned for recess till Half Past Five of the Clock.

The House re-assembled after recess at Half Past Five of the Clock.

[MR. DEPUTY. SPEAKER IN THE CHAIR].

श्री. व्ही. डी. देशपांडे:—अध्यक्ष महोदय, जो बादल अब तक हिंदुस्तान के मशरीक में और मगरीब में मंडरा रहे थे वे आज रास्त हिंदुस्तान पर आना चाह रहे हैं। जो खतरा हमारे आसपास के मुल्कों को अमेरिकन कार्यवाहियों की वजह से पिछले पांच साल से पैदा हुआ है, वह आज रास्त तौर पर हिंदुस्तान पर आ रहा है। और अमेरिका के अुस जारहाना अेकदाम के खिलाफ हमें सोचने का मौका आ गया है। कल ही पंतप्रधान नेहरू ने पार्लिमेंट में यह कहा है कि अब हम अमेरिकन फौजी अफसरों को गैरजानिबदार नहीं समझ सकते अुनके अल्फाज ये हैं।

“We think a situation has arisen when no officer of the U. S. Army can be considered as neutral.”

यह भी सुना गया है कि पंडित नेहरूने चेंबर ऑफ कामर्स, कलकत्ता, की मीटिंग में यह कहा है कि अेक खास हालत में किस हद तक मआशी अिमदाद हम बाहर से ले सकते हैं, और कितनी लेनी चाहिये अिसको भी हमें सोचना पडेगा। यह जो खियालात पंडित नेहरू ने जाहीर किये हैं अुससे हमें पता चलेगा कि कुछ खास दौर से गुजर रहे हैं। अेक जमाना था कि अमेरिका के गुणगान से हमारा मुल्क भरा हुआ था। हम अमेरिका को अपना सबसे बडा दोस्त समझते हुअे अुनका स्वागत किया करते थे। लेकिन पिछले अेक साल में जो वाक्यात हमारे सामने आये हैं अुससे जिस गहरी नींद में हम पडे हुअे थे अुससे हम आज जाग रहे हैं। हमें जो पहला तजस्बा हुआ वह कश्मीर के अंदर हुआ। शेख अब्दुल्ला पर भरोसा रखते हुअे आज तक अपनी कौमी जद्दोजहद की कोशिश के तौर पर हम अुनकी अिमदाद करते रहे और वहां की अक्वाम जो वहां की जमीनदारी के खिलाफ और वहां के महाराजा के खिलाफ लड रही थी अुसका साथ देते रहे। हम यह समझ रहे थे कि जिस जमहूरियत को हम कायम करना चाहते हैं अुसी रास्ते पर हिंदुस्तान के अेक हिस्से के तौर पर कश्मीर आगे बडेगा। लेकिन हमारा यह सुख-सपना अेक दिन टूट गया। हमने देखा कि अमेरिका ने वहां अपनी कार्यवाही शुरू की और यह कोशिश की कि वहां अपने जंगी मनसूबों के लिये अड्डे कायम कर सकें, और अिस हिस्से को हिंदुस्तान से अलग करें। वे चीजें खतम हुओं न हुओं कि हमने सुना कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका का मुआहदा हो रहा है। बहुत से लोगों को अुस वक्त अैसा मालूम हुआ कि अैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका को हम अपना सबसे बडा दोस्त मानते हैं और अमेरिका भी समझती है कि अेशिया में हिंदुस्तान अेक अैसा मुल्क है जिसको दोस्ताना तौर पर रखना चाहिये और हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात अुसके साथ बढ़ाने चाहिये। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा होने की खबर हमने सुनी और आज जो कुछ हो चुका है अुससे अब हम अपनी गहरी नींद से जाग अुठे हैं और सोच रहे कि यह जो तरीका अमेरिका की तरफ से अखितयार किया जा रहा है अुसके सिलसिले में क्या किया जाय। मैं हाअुस से बताना चाहता हूँ कि अमेरिका की कार्यवाहियां आज हमें नये तौर पर महसूस हो रही हैं लेकिन अुसका आगाज १९४५ में जब दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ अुसी वक्त से हुआ है। और जिस हिटलर को दुनिया की अक्वाम ने शिकस्त दी थी अुसी हिटलर का विरसा लेकर अमेरिका दुनिया के अंदर सब दुनिया पर हावी

होनेकी औषसि आगे कदम अठाती गयी। आप अगर अिस अमेरिका की कार्यवाहियों को जंगे अजीम नंबर दो के खतम होने के बादसे देखेंगे तो पता चलेगा कि अुनकी कार्यवाही हमेशा दो तरह की रही है। अेक तरफ दुनिया में जो सोशलिस्ट मुल्क है या जहां जहां अ्वाम की जमहूरियत पसंद हुकूमतें कायम हुआं हैं, मसलन् सोवियट रूस और पीपल्स चायना और दीगर मुमालिक, अुनके खिलाफ अेक महाज खडा किया जाय। अिसके साथ साथ अपने बेगार को बढाने के लिये, ज्यादा मंडियों को हासिल करना, अपने सरमायेदारों के अेक्सप्लॉयटेशन को आगे बढाने के लिये दुनिया में जितने पिछडे हुये मुल्क हैं अुनको अपने काबू में लाने की कोशिश करना, यह भी दूसरी कोशिश अमेरिका की तरफ से हुआ है। यानी १९४५ से ही हिटलर का विरसा लेकर अमेरिका आगे बढ रही है। हिटलरने यही किया था कि अेक तरफ दुनिया में सोवियट रूसके खिलाफ नारा देते हुअे दूसरी तरफ यह अैलान किया कि हमें कॉलनीज नहीं है, हमारी बढती हुआ आबादी के लिये जगह नहीं हे लिहाजा हमें अेक नया मुल्क मिलना चाहिये। अिस तरीके पर हिटलर आगे बढा। आज अमेरिकन साम्राज्यवादी भी बिल्कुल अुसी तरीके से दुनिया के अंदर आगे बढ रहे हैं। आज पाकिस्तान और अमेरिका का जो मुआहदा हुआ है अुसे हम अपने लिये अेक गाअिड के तौर पर न देखें तो आयंदा जो कुछ होनेवाला है अुसके बारे में हमें आगे जो कदम अठाना चाहिये वह ठीक तरह से नहीं अुठा सकेंगे अमेरिका की तरफ से दूसरे जंग के बाद मिलीटरी मुआहदा हर जगह करने की कोशिश की गयी। यूरप के अंदर अेक यूरप अमेरिका पैक्ट बनाया गया। अुसके बाद मिडिल अीस्ट में मेडो के नाम से अेक पैक्ट बनाने की कोशिश की गयी। अुसके बाद जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलंड के अुस हिस्से में पैसिफिक पैक्ट बनाने के बारे में कोशिश की गयी। लेकिन छोटीसी कामयाबी से 'अेन्सज' नाम से अेक पैक्ट बनाया गया। अिसके आगे वे वहां नहीं बढ सके। यह कोशिश अिसलिये थी कि यूरप से लेकर जापान तक अेक अैसी पूरी संकल तैयार की जाय जो कि मौका आने पर अेशिया के अुन तमाम मुल्कों के खिलाफ अिस्तेमाल की जा सके जो अभी पिछडे हैं जिन में से कुछ अभी अभी आजाद हुअे हैं या जो अभी आजाद नहीं हुअे हैं और आजादी के लिये लड रहे हैं और जो मुल्क अेशिया के मुल्कों को आगे जाने में मदद दे रहे हैं। अेशिया के तमाम मुल्कों को धोखा देने के लिये अुनको आजाद न होने देने के लिये, जो आजाद हुअे हैं अुनकी आजादी खतम करने के लिये अमेरिका ने यह कोशिश की। अिसका मकसद अेकतरफ सोवियट रूस और पीपल्स चायनाके खिलाफ अेक कार्डन (cordon) तैयार करने का भी था। लेकिन मैं हाअुस को बताना चाहता हूं कि अेक जमाने में हिटलर ने भी अपने दावे के साथ दुनिया के तमाम मुल्कों को अपने पंजे में लाने की कोशिश की थी। लेकिन दुनिया को अ्वाम ने अुसको पहचाना। आज वही चीज हमारे सामने फिर से आ रही है। अमेरिका अपने कदम हर जगह बढाते जा रहा है। अिस वक्त हाअुस के सामने अिस चीज को रखना गैरमुनासिब न होगा कि अेक तरफ रूस और चायना के खिलाफ कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ खुद अमेरिका और अिंग्लैंड में आपस में जंद्ोजहद जारी है। और अुसके फलस्वरूप अंग्रेजों के लिये मंडियां हासिल करनेके लिये अमेरिकाकी तरफसे जो कोशिश हो रही है अुसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अिन दो तरीकों से आज अमेरिका दुनिया में आगे बढ रहा है। अिस पसमंजर में न अपनी आजादी के लिहाज से और अपने मुल्क की कूवतों को बढाने के लिहाज से अमेरिका कि कोशिशों की तरफ देखना चाहिये। हमने १५ अगस्त १९४७ में अपनी अ्वाम की जंद्ोजहद से और दुनिया के अंदर जो जमहूरी ताकत पैदा हुआ थी अुसकी वजह से जो कुछ सिपासी हुकूम हासिल

किये अन्को ज्यादा मजबूत करने के लिये और जो हमारी पस्त मआशी हालत है अुसको खतम करने के लिये आगे कदम अुठाना शुरू किया । हमारे सामने यह सवाल था कि हमारे मुल्क की आयंदा हम तरक्की कैसे कर सकेंगे, जो बर्तानिया के मआशी बंधन हमारे अपर है अुनको कैसे तोड सकेंगे और मुल्क के अंदर जो हमारी अव्वाम का स्टैंडर्ड आफ लिविंग है अुसको कैसे बढा सकेंगे । हमने आगे बढने की कोशिश की लेकिन हम कामयाब न हो सके । इसी वक्त हिंदुस्तान अेक बहुत बडा सनअती और ताकतवर मुल्क न बने इस लिये अमेरिका की तरफ से, साम्राज्यवादी अमेरिका की तरफ से, कोशिशें जारी थी । हिंदुस्तान ताकतवर न हो सके इसलिये अेक जमाने मे अंग्रेजोंने भी कोशिश की थी । अुन्होंने हिंदुस्तान की तकसीम की और हर जगह अपने सियासी और मआशी तसल्लुत को कायम रखते हुअे पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को कमजोर रखने की कोशिश की । लेकिन हिंदुस्तान मे जो जमहूरी कूव्वतें हैं, हिंदुस्तान की अव्वाम ने अेक जमाने में साम्राज्यावादियों के खिलाफ लड कर जो ताकत हासिलकी है, अुसकी वजह से अमेरिका का अैसा तसल्लुत हिंदुस्तान के अपर कायम नहीं हो सका जिस तरह वे पाकिस्तान में कायम कर सके हैं । जो अमेरिका पिछले तीन साल में हिंदुस्तान पर अप नी पकड कायम करने में कामयाब न हो सका, अुसने यह अेक नया रास्ता आज ढूँढा है और पाकिस्तान अमेरिका का मुआहदा अुसीका नतीजा है । इस मिलीटरी मुआहदे का मकसद जहां अेक तरफ यह है कि दुनिया की अव्वामी जमहूरियतों के खिलाफ अेक कॉर्डन तैयार किया जाय, वहांयह भी मकसद है कि अमेरिका के जो जंगी मनसूबे हैं अुनके अंदर हिंदुस्तान को खींचा जाय । आयसेनहोवर से जो पत्र पंडित नेहरु को आया है अुसमें अुन्होंने कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान को हमने अिमदाद दी है अुसी तरह आपको भी देने के लिये हम तैयार हैं लेकिन इस सिलसिले में पंडित नेहरु का जवाब बिल्कुल साफ साफ है कि किसी भी मुल्क की आजादी बाहरी फौजी अिमदाद पर कायम नहीं रह सकती । हम किसी की अिमदाद लेकर आगे नही बढना चाहते हैं हम अैसी अिमदाद नहीं ले सकते और आज अमेरिका से पाकिस्तान को जो मदद दी जा रही है अुसको भी ठीक नहीं समझते । बहुत से लोग समझते हैं कि जवाब देने की हमें क्या जरूरत थी ? अगर हम अुनसे फौजी मदद लें तो क्या हर्ज है ? मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह नमहसूस करनेवाले लोग हों । वे समझते होंगे कि हम अमेरिका से अिमदाद लें तो हम ताकतवर बनेंगे और कश्मीर का मसला हम हल कर सकेंगे । लेकिन मुझे इस वक्त वह कहानी याद आ रही है जिसमें बताया गया है कि किस तरह घोडे ने अेक जंगली जानवर को खतम करने के लिये अिनसान की मदद मांगी और हमेशा के लिये अिनसान को अपनी पीठ पर सवार कर लिया । मसले के तमाम पहलुओं को मैं हाजुस के सामने नहीं रखना चाह रहा हूं । दूसरी भी अेक मिसाल मैं दे सकता हूं । अेक जमाने में फिलिपिन्स ने स्पेन के खिलाफ अपनी आजादी की रक्षा के लिये अमेरिका की अिमदाद मांगी और बाद में फिलिपिन्स अमेरिका की अेक नौआबादी बन गया । आज पाकिस्तान समझ रहा है कि अमेरिका की अिमदाद लेकर वह कामयाबी हासिल कर सकेगा । मुझे पाकिस्तान की अव्वाम से अपील करनी है कि जिससे पाकिस्तान आगे बढनेवाला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान दुनिया के सब से बडे ताकतवर और साम्राज्यवादी हुकूमत अमेरिका के हाथ का अेक खिलौना बन जायगा, बल्कि मैं कहूंगा कि करीब करीब वह आजही अैसा खिलौना बन गया है । इससे पाकिस्तान की अव्वाम की बहबूदी होनेवाली नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के साथ रहते हुअे हिंदुस्तान की अव्वाम की जद्दोजहद के कारण पाकिस्तान को जो आजादी मिलसकी है वह भी खतम हो जायगी । शायद यह चीज पाकिस्तान की अव्वाम को भी

पसंद नहीं है। औस्ट बंगाल के अलिवेशन के नतायज यही बता रहे हैं। पाकिस्तान का हुक्मरान तबका समझ रहा है कि अमेरिका की अिमदाद से पाकिस्तान की बहबूदी होगी। लेकिन औस्ट बंगाल ने यह बतलाया है कि पाक-यू. अंस. अं. पैक्ट के पीछे वह खडा नहीं है। मुस्लिम लीग वहां हारी है और मुत्तहादी पार्टी है अुसने अबतक की खबर के मुताबिक ५१ सीटें हासिल की हैं। जिससे जाहीर होता है कि पाकिस्तान की अक्वाम समझती है कि अमेरिका की अिमदाद जो पाकिस्तान ले रहा है वह अुसकी आजादी के खिलाफ जानेवाली चीज है। वहां की अक्वाम भी यह महसूस करती है कि जिससे पाकिस्तान की बहबूदी नहीं होगी, बल्कि अुनकी आजादी खतम हो जायगी, और अंग्रेजों के पंजेसे निकल कर अमेरिका के पंजे में पाकिस्तान जा रहा है। इसीलिये पंडित नेहरूने अमेरिका की अिमदाद को लेने से अिनकार किया। इस असेंब्ली में भी इस ख्याल का अिजहार करता हूं कि जो साम्राज्यवादी अमेरिका अपनी अिमदाद देकर हिंदुस्तान को अपने सियासी कामों की अेक संकल बनाना चाहता है और हमारी आजादी पर जरब लगाना चाहता है अुसकी अिमदाद हम हरगिज नहीं ले सकते और न लेंगे। किसी साहब ने कहा कि हमारा मुल्क गरीब है और हमारे पास सरमाया नहीं है। बगैर सरमाया लिये हम कैसे आगे बढ सकते हैं ? जिस प्रश्न के लिये मेरा जवाब यह है कि अगर किसी अिमदाद की वजह से हमारी आजादी पर असर होता है, हमारी आजादी पर जरब लगता है, तो ऐसी अिमदाद न लेने के नतीजे में अगर हमको भूखा भी मरना पडे तो हम भूखे मरेंगे लेकिन आजादी पर असर करनेवालों का डटकर मुकाबला करेंगे। इसी ख्याल से हम सब को आज आगे बढना है। पंडित नेहरूने इस सिलसिले में जो पॉलिसी जाहीर की है अुसको, अपनी ताअीद जाहीर करने के लिये आज हाअुस के सामने मैंने इस रेजोल्यूशन को लाया है।

दूसरी अेक चीज मैं हाअुस के सामने रखना चाहता हूं। बहुत से लोग यह समझे कि पाक-अमेरिका के जिस पैक्ट से हमको धोखा नहीं है बल्कि रूस और चायना को है। हमें जिससे क्या करना है ? जैसा मैंने दूसरी अेक तकरीर के सिलसिले में कहा था कि अिन्सान के खून का अेक दफा शेर को चस्का लग जाय तो वह यह नहीं देखता कि जिस गांव का आदमी अच्छा है या अुस गांव का। वह किसी को भी अुडाता है। मुझे बहुत बडा शक होता है कि कोरिया की लडाअी में पस्त होने के बाद आज अमेरिका में जो बेरोजगारी बढ रही है, चीजों की कीमतें गिर रही हैं, जंग का सामान पडा है अुसको मुनाफे से बेचने के लिये शायद दुनिया के अंदर और कहीं छोटी मोटी जंग शुरू करदी जाय जिस ख्याल से अमेरिका की कोशिश आगे बढती जा रही है। ऐसी हालत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आज जो ताल्लुकात हैं अुनको देखते हुअे अमेरिका के लिये अिन दो देशों के सिवा दूसरी कौनसी जगह अच्छी हो सकती है जहां वह लडाअी शुरू कर दे ? जिस साम्राज्यित की यह ट्रेडीशन है कि वह दुनिया के लोगों को आपस में लडाये और खुद मुनाफा कमा लें अुसके लिये क्या यह संभव नहीं है कि वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लडाकर अपने जंगी सामान के लिये अेक खासा मार्केट खुला करे ? किसीने कहा है कि मौत के बेपारी अमेरिकन साम्राज्यवादी यह चाह रहे हैं कि अपने माल को बेचने के लिये हर जगह दुनिया के अंदर जंग को चलाया जाय। इस चीज को अगर हम नजरअंदाज करें और सिर्फ इसी ख्याल में रहें कि जिससे चीन और रूस को ही धोखा है तो हम बडी भारी गलती करेंगे। आज जो अीरान में हुआ है वही कल हिंदुस्तान में होने के अिमकानात पैदा हो सकते हैं। अीरान के अंदर मुसादिक की हुकूमत ने आजाद अीरान के कभी मसले हल

किये। अीरान की आजादी पर कअी साल से हावी होनेवाले अंग्रेजों को वहां से खतम किया, अपनी मुल्क की तरक्की के लिये अुसने तमाम जरायों को अपने हाथ में लिया और अेक जमहूरी दौर वहां कायम कराया। लेकिन हम देखते हैं कि वहां भी अमेरिका ने मुसादिक को अुखाड ने के लिये वहां कि अेक विरोधी सियासी पार्टी को मिलीटरी अिमदाद दी और जिस मुसादिक को वहां की अव्वाम कि मेजारिटी ने मुल्क का कारोबार जिस तरह से वह चाहे अुस तरह से चलाने के लिये अधिकार दिया था, अुसको अुखाड फेंका गया और पूरे मुल्की के खियालात के खिलाफ जाकर अमेरिका के तहत अेक दूसरी हुकूमत वहां कायम की जा रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो हालत है अुसमें वहां जो हुआ वह होना अुतना मुमकिन नहीं है। हमारी अेक जमहूरी कूव्वत है, जद्दोजहद है, अेंटी अिम्पेरिअेलिस्ट ट्रेंडीशन्स है, अिन तमाम का ख्याल करते हुअे अमेरिका के लिये हिंदुस्तान का अीरान बनाना आसान नहीं है। लेकिन जिस तेज रफ्तार से अमेरिका हर जगह आगे बढ रहा है और जो आसपास के हालात बदलते हुअे नजर आ रहे हैं अुससे यह मालूम हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान को अेक तरह से घेरा डालते हुअे अमेरिका जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर अुनके हवाअी अड्डे हैं। हमारे मुल्क के अंदर गोवा का भी अिस्तेमाल किया जा रहा है। अुधर जापान के अंदर अिंडोचायना में और आसपास में अमेरिका के अड्डे आज भी कायम हैं। अिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अतराफ अमेरिका का घेरा पडा हुआ है और अगर आंतरराष्ट्रीय हालात अिसी तरह से खतरनाक होते चले जायें तो अमेरिका के लिये हिंदुस्तान पर दबाव लाना मुश्किल नहीं है। अिस तरह से अमेरिका की पकड हमारी आजादी को न सिर्फ बैरूनी तरीके से बल्कि अंदरूनी तरीके से भी खतरा पैदा करती है। अिसीलिये पंडित नेहरू ने कहा है कि कश्मीर के अंदर जो अमेरिकन न्यूट्रल्स हैं अुनको हम न्यूट्रल्स नहीं समझ सकते। वे यहां रहकर हमारे तमाम फौजी कारोबार को देख सकते हैं, हमारे यहां के स्ट्रेटेजिक पोस्टस् को देख सकते हैं, हमारी फौजी कॉन्फीडेन्शियल चीजों को जान सकते हैं और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात रख सकते हैं। अुनको हम अपने दोस्त कैसे समझें? अुनसे हमे धोखा नहीं है अिस चीज का भी यकीन हम कैसे रख सकते हैं? आयसेनहोवर, वजीरे आजम अमेरिका और मोहम्मद अली वजीरे आजम पाकिस्तान, दोनों ने कहा है कि हम जो अिमदाद दे रहे हैं और ले रहे हैं, वह किसी मुल्क के खिलाफ लडाअी करने के लिये नहीं है। अगर अैसा नहीं तो क्या वजह है कि अिस तरह से जब पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि कश्मीर का मसला तय करने के लिये हमने दुनिया के सामने, यूनो के सामने, खुलेआम रख दिया है, अुसके बावजूद हिंदुस्तान पर दबाव लाने के लिये अिस तरह से फौजी अिमदाद ली और दी जा रही है? दो साल पहले हिंदुस्तान ने अिस चीज को साफ कर दिया है कि यूनों पर भरोसा रखते हुअे वह अिस मसले का हल पा सकेगा। लेकिन हम देखते हैं कि दो साल से अमेरिकन साम्राज्यवादी कश्मीर के मसले को हल करने के रास्ते में मुसलसिल रोडे अटका रहे हैं। अेक साल पहले हिंदुस्तान खुश था। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री मोहम्मद अली देहली आये और पंडित नेहरू भी कराची गये थे और अैसा मौका पैदा हुआ था कि हम आपस मे बातचीत करके अपने सवालात हल कर सकें लेकिन अैसा होना अमेरिका के लिये ठीक नहीं था। अमेरिकाने पाकिस्तान से जो दोस्ताना ताल्लुकात रखे अुनकी वजह से और अमेरिका की जारहाना पालिसी की वजह से यह चीज न हो सकी और तब से दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे। अिन चीजों को हाअुस के सामने रखते हुअे मुझे यह कहना है कि हम अिनडिफरन्ट हो कर सुस्ती से आज के बदलते हुअे हालात की तरफ नहीं देख सकते। हमें अिस सवाल की तरफ तवज्जह देनी

पडेगी और अुसकी तरफ देखने का जो हमारा तरीका है अुसको भी साफ करना पडेगा। मैं यह बताअूंगा कि आज मुल्क के अूपर सिर्फ बाहर से ही खतरा नहीं है, बल्कि अंदर से भी खतरा है और वह है अून तमाम फिरकेवारानां अिदारों से जो अिन तमाम हालात में हिंदुस्तान का जो सेक्यूलर स्टेट है अुसके अंदर रहनेवाले मुस्लिफ मजहब के लोगों में झगडे पैदा कराना चाहते हैं। हिंदुस्तान का अेक रिपब्लिक कायम हुआ है और जो हमारी कौमी ट्रेंडेशन है अुसने हमको सिखाया है की मजहब के लिहाज से हम किसी में फर्क नहीं करते। जाति और मजहब को ख्याल में रखते हुअे हमने कभी हिंदुस्तान की कौमी जद्दोजहद में नहीं सोचा, बल्कि हमेशा यह सोचा है कि जो चूसनेवाले हैं अुनके खिलाफ तमाम अुव्वाम का अेक महाज खड़ा होना चाहिये। लेकिन आज के हालात का फायदा अुठाते हुये कुछ फिरकेवारानां अनासिर आगे बढ़ना चाहते हैं। अिन फिरकेवारानां अनासिर से हमें तजरूबा है कि वे पाकिस्तान की अुव्वाम के खिलाफ हिंदुस्तान की अुव्वाम को मजहब के नाम पर अुठाना चाहते हैं और अिसी बिना पर अंग्रेजों के जमाने में अुन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और हमारे कौमी जद्दोजहद के खिलाफ नारे लगाये थे। अिसलिये अेक तरफ हमारे मुल्क के बाहर से जो खतरा है अुसके खिलाफ भी हमें तैयारी करना है और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर जातीयतावादी और मजहबी खियालात के लोगों के खिलाफ अेक बहुत बड़ा मुत्तहिदा महाज खड़ा करना है। अिसलिये मैंने अपने रेजोल्यूशन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात पर जोर दिया है। हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुस्तान की हद तक ही खतरा नहीं है, बल्कि साअुथ अीस्ट अेशिया में जो अमेरिका तेजीसे बढ़ता जा रहा है अुसकी वजह से पूरे साअुथ अीस्ट अेशिया को धोखा हो गया है। सिर्फ हिंदुस्तान का ख्याल रखकर अगर हम अिस पाक-यू.अेस.अे. पॅकट के खिलाफ आवाज अुठायेगे तो अानेवाली परिस्थिति का मुकाबला हम नहीं कर सकेंगे। अेशिया के सब मुल्कों को जिन्होंने पिछले पचास साल से कौमी जद्दोजहद में हिस्सा लिया है और आजाद हो गये हैं, और आज भी आजादी के लिये लड़ रहे हैं अून सब को—बर्मा, अिंडोनेशिया अिंडो चायना और दोगर मुसलिक को अेक जगह लाना पडेगा क्योंकि अिस साम्राज्यित का हमें मुकाबला करना है वह दुनिया के दो सबसे बड़ी ताकतों में से अेक है। अकेले हिंदुस्तान को अुसका मुकाबिला करना मुश्किल है। अमेरिका की तरफ से जो कदम आज अुठ रहा है अुसको रोकने की ताकत आज किसी अेक मुल्क में नहीं है, बल्कि अुसके लिये दुनिया की आजाद पसंद अुव्वाम का अेक बहुत बड़ा महाज हमें खड़ा करना पडेगा। अिसलिये मैंने अिस रेजोल्यूशन के अंदर (.....develop Indo-Pakistan friendship, Asian solidarity and World Peace.) के अल्फाज रखे हैं।

दूसरी चीज मुझे यह रखना है कि दुनिया के अंदर आज जो अमन कायम करने की तहरीक है अुसको आगे बढ़ाना चाहिये। हम चाहते हैं कि हमें अपने मुल्क के अंदर आजादी हो ताकि हम अपने दिल के मुताबिक चाहे जैसी हुकूमत कायम कर सकें। दूसरे मुल्कों को अिसमें मदाखलत करने का अेख्तियार नहीं होना चाहिये और यहां दूसरे मुल्कों को अपना तसल्लुत कायम करने का मोका भी नहीं होना चाहिये। लेकिन साम्राज्यवादी राष्ट्र अपनी मंडियों को कायम रखने के लिये, दुनिया के मुल्कों की आजादीपर जरब रखने के लिये, अुनके अंदरूनी मामलात में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अुनको अपने पंजे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हममें से हर अेक, जिस तरह चाहे किसी भी प्राप्ति का हो, अपने मुल्क की आजादी को सब से बड़ी चीज समझता है।

और जब कभी मुल्क की आजादी पर हमला होने के भिमकानात पैदा होंगे तो बिना किसी पार्टी बाजी या मजहब के खियाल से हम सब को अंक होकर उसका मुकाबला करना चाहिये। किसी चीज को जाहीर करने के लिये यह रेजोल्यूशन हाउस के सामने रख रहा हूँ। हाउस का ज्यादा वक्त न लेते हुये इस रेजोल्यूशन का जो आखरी ऑपरेटिव पार्ट है उसकी तरफ हाउस को तबज्जेह दिलाना चाहता हूँ। आज सिर्फ असेम्बली में बैठकर इस तरह के करास्वाद पर बहस करने से, या बाहर मीटिंग लेने से, इस मसले को हम हल नहीं कर सकते। पंडित नेहरू ने और दूसरी जमे-हूरी पार्टियों ने पिछले छः महीनों में इसके खिलाफ पुरजोर आवाज बुठाई है। लेकिन अफ-सोस की बात है कि जो अमेरिकन साम्राज्यवादी अपना आस्था कदम अंठा रहे हैं वे अब तक हमारी आवाज को नहीं सुने हैं। जब हमने आवाज बुठाई तो हम यह अुम्मीद कर रहे थे कि हमारी दोस्ती का अेहतुराम किया जायगा और इस तरह का फेक्ट जो बनाया जा रहा है उसको रोका जायगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब साम्राजियत के सामने अपने फायदे का संवाक्य आता है तो वह लोगों की दोस्ती को ठुकरा सकता है। ऐसी हालत में हमको एक मुत्तहिदा तौर पर कदम अठाना पड़ेगा। आज हमारे मुल्क पर किस तरह का संकट आयेगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं यह हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारे मुल्क पर किसी भी किस्म का संकट आ जाता है तब हम सब को अंक होकर आगे बढ़ना होगा और अपने मुल्क का रक्षण करना पड़ेगा। इस काम में हम सब को साथ रहना चाहिये।

आखिर में मैं हाउस से अपील करूंगा कि इस चीज को हुक्मते हिंद पर बाजे करना चाहिये कि अपने मुल्क को और मुल्क की आजादी को बरकरार रखने के लिये उसको ज्यादा मजबूत करने के लिये, हमें जल्द से जल्द कदम अठाना चाहिये। आज जो हमारे मुल्क में अमेरिकन निरीक्षक हैं वे अब-यहां नहीं रह सकते। मैंने इस रेजोल्यूशन में अमेरिका के साथ जो ताल्लुकत है उनको तोड़ना चाहिये इसके बारे में जो जुमला था उसको निकाल दिया है, लेकिन इसके पीछे जो सेंटिमेंट है उसको मैं इस वक्त हाउस के सामने रखे बगैर नहीं रह सकता। अगर अमेरिकन निरीक्षक हमारे देहातों के अंदर हैं, फौज के अंदर हैं, सबअतों के अंदर हैं, और सनअतों को जानते हैं, अगर उनके टेकनिशियन्स हर जगह घूमते हैं, अगर उनके अग्निफरमेशन ब्यूरोज शहरों में खोले गये हैं, मुल्क के अखबारों में अपने-नुमाजिदों को छेड़कर हमारे मुल्क की सेक्यूलर पॉलिसी के खिलाफ और हमारी जमहूरी पॉलिसी के खिलाफ लिख सकते हैं तो ऐसी हालत में हम अमेरिका का भरोसा कैसे कर सकते हैं? हिंदुस्तान के खिलाफ आज अमेरिका और दुनिया की अब्बाम में सब से ज्यादा प्रचार जो करते हैं वे उनके यहां के अजेन्ट ही करते हैं। पंडित नेहरू की होम पॉलिसी के खिलाफ दुनिया की अब्बाम को तैयार करने के लिये सोजाना अखबारात के स्तंभ के स्तंभ लिखे जाते हैं और अब्बाम को बताया जाता है कि पंडित नेहरू कम्युनिस्ट हैं। हम तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन पंडित नेहरू कम्युनिस्ट हैं या नहीं यह तमाम लोग जानते हैं। लेकिन पंडित नेहरू और हम दोनों चाहते हैं कि हम अपनी आजादी बरकरार रखें और उसके खिलाफ कोई हमला करने की हिम्मत करे तो उसके खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर खड़े होकर लड़ें। ऐसी हालत में मैं हाउस से कहूंगा कि हमें बहुत ही सौच समझ कर और सूचत रह कर आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। हम मुल्क के अंदर यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी अमन की पॉलिसी के खिलाफ कोई यहां प्रचार करे और हमारे अखबारात को सबसीडी देकर

हमारे ही खिलाफ लिखने के लिये अूनको मजबूर करें। इस चीज पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे मुल्क के अंदर अमेरिकन प्रचार जारी है और इसके लिये यहां अमेरिकन अजेंट्स भेजे हुए हैं। यही बात हिटलर ने सन १९३७ में की थी। आपको मालूम है कि दूसरा महायुद्ध शुरू होते ही किस तरह से यूरोप के देश अंक के बाद अंक गिरते गये। इस की वजह सिर्फ यह नहीं थी कि हिटलर के पास बहुत अच्छी फौज थी। अच्छी फौज तो थी लेकिन वह बहुत कम थी। लेकिन सब से बड़ी वजह यह थी कि हर मुल्क को अंदरूनी तौर पर, नैतिक तौर पर, अुसने अपने हाथ में लिया था। अुसने मुल्क के अंदर मुस्तफिल सियासी पार्टियोंको करप्ट किया था, और अपने अजेंट्स हर जगह रखे थे और अक पंचमस्तंभ कायम किया था। इस वजह से वह यूरोप के अंदर जल्दी कामयाबी हासिल कर सका। इस चीज को हमें आज ही सोचना पड़ेगा। मुल्क के सामने जो खतरा है अुसका सामना करना है तो पहले फिरकेवाराना जहूनियत के लोगों के खिलाफ कदम अुठाना चाहिये और अूनका मुकाबला करने के लिये अब्बाम को तैयार करना चाहिये।

आखिर में अंक बात कहते हुए मैं अपनी तकरीर खतम करूंगा। अगर कोअीसाम्राज्यवादी मुल्क हमारी तरफ अंक गीदड़ दृष्टि से देखने की जो जुरंत करता है अुसकी वजह क्या है? यही है कि हमारी माशियत पिछड़ी हुई है, हमारे मुल्क के सनअतों की तरक्की नहीं हुई है, इसलिये बाहरी मुल्क हमें यह टेम्पटेशन देते हैं कि आप हमारी मदद लीजिये ताकि आप तरक्की कर सकेंगे। इस बहाने से वे हमारे मुल्क के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। नव आवादियों को अंग्रेजों को यह विरसा है कि वह मआशी तौर पर अुनके कब्जे में रहें। हम सोचते हैं कि अगर बर्तानिया हमारे सवाल हल नहीं कर सकता तो हम और किसी देशके पास जायें और अुसकी मदद लें। यह जो हमारा बँकवर्डनेस है, वही साम्राज्यवादियों को हमारे मुल्क पर नजर डालने के लिये और अुसको अपने कब्जे में करने के लिये अच्छा कारण हो जाता है। अंक तरफ पाक यू. अेसए. पॅक्ट के खिलाफ आवाज अुठाते हुए मुल्क के अंदर जो फिरकेवारीना अिदारे हैं अुनके खिलाफ हमें लड़ना है और साथ ही साथ अमेरिकन पेनिट्रेशन का भी मुकाबला करता है। लेकिन अुसके साथ साथ मैं यह भी अपील करूंगा कि जिस बुनियादी बँकवर्डनेस की वजह से साम्राज्यवादी लोग हिंदुस्तान को अपना अड़्डा बना सकते ह, अुसके खिलाफ हम सब को मुत्तहद हो कर लड़ना पड़ेगा और आगे कदम बढ़ाना होगा। मुझे इसकी अुम्मीद है। मैं मायूस नहीं हूं। मैं हिंदुस्तान में देख रहा हूं कि बावजूद इसके कि हिंदुस्तान के अंदरूनी पॉलिसी के बारे में मतभेद है फिर भी जब मुल्क का कौमी सवाल सामने आता है तो मुल्क की तमाम जमहूरियत पसंद पार्टियां अंक जगह अने के लिये तैयार होती हैं। अंक जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिये अंक मुत्तहदा महाज बनाते हुए तमाम पार्टियां और तमाम तबके जिस तरह से अंक जगह आया करते थे अुसीकी कुछ झलक हम आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने में पा रहे हैं। देहली में पार्लिमेंट के अंदर जब यह मसला आया तो तमाम पार्टियों ने पंडित नेहरू की इस सिलसिले में जो पॉलिसी है अुसका खैरम-कदम किया और अुसकी पुरजोर ताअीद की। इसी तरीके से हम हदराबाद और दूसरी रियासतों में भी कदम अुठाये तो मुझे यकीन है कि इस तरह से जो हमारी बढ़ती हुयी ताकत है वह

* شری لکھن کزنڈا (آصف آباد - عام) - مسٹر اسپیکر سر- جو ریزولوشن ہاوز کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس میں میں نے بھی ترمیم پیش کی ہے۔ جس طرح سے آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے کھلمے نبھاؤں (शब्दों) میں پرستھی (परिस्थिती) کاورنن (वर्णन) کہا ہے اسی طرح میں بھی اپنا نکتہ نظر اسوان کے سامنے رکھوں گا اور وسراس (विश्वास) کروں گا؟ کہ آنریبل ممبرس اس کو تساتی (शांती) کے ساتھ سنیں گئے۔ اس لئے کہ جب میں پچھلے زمانے کو یاد کرنا ہوں تو محسوس کرنا ہوں کہ جب میں تقریر کرنے کے لئے کھڑا ہو ڈاھوں تو اس طرف کے آنریبل ممبرس انٹریپٹ (Interrupt) کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ ایسا نہیں کیا جائیگا۔

پاک امریکی معاہدہ کا مسئلہ بہت گہری جڑیں لئے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ شمال اور مشرق کی طرف سے کچھ فیسیزم (Fascism) بہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے جس کو دیکھ کر اس کے مقابلہ کے لئے ایک سامراجیت کی لہر شمال و مغرب کی جانب سے بڑھ رہی ہے۔ یہ دو قوتیں ہیں جو متحدہ محاذ قائم کرنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں کسی ملک کی سیاست کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن پاک امریکی پیکٹ (Pact) کے پیچھے ایک گہری سازش تھی۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے یا یہ شبہ کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو درخواست کرنا اور امریکہ میں جو پاکستان کا نمائندہ ہے اس کو لاکر وزیر اعظم بنانا اور اس کے بعد گورنر جنرل کا امریکہ جانا اور وہاں پاک امریکی پیکٹ (Pact) کا افشاء ہونا اور اس کے چند دن بعد اس کا حقیقت بن جانا یہ سارے واقعات درشتی میں لائے جائیں تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری باتیں پری پلانڈ (Pre-planned) کے تحت ہوئی ہیں اور پاکستان کو وہاں کے عوام کی مرضی کا خیال کئے بغیر اور ان کے خیالات کو پیش نظر نہ رکھتے ہوئے امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔

چنانچہ ایسا ہوا۔ جو کچھ ہوا اس کی ساری ذمہ داری محض امریکہ یا پاکستان پر ہے میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ اس کی ذمہ داری اگر مساوی نہیں تو کم از کم بڑی حد تک ریشیا پر اور ریشیا کے ڈھنگ سے سوچنے والوں پر بھی ہے۔ چنانچہ اس کے بڑے دور رس اثرات ہونے کی صورت نظر آتی ہے۔ ہندوستان جو کسی بلاک کے ساتھ

ہونا نہیں چاہتا اور اپنی ایک آزاد پالیسی رکھتا ہے دنیا کے حقیقی امن کا اگر کوئی علمبردار ہے تو وہ صرف ہندوستان ہی ہے۔ نہ تو رشتہ ہے نہ امریکہ۔ چنانچہ جس بڑی قوت کو دونوں ممالک بھی پسند نہیں کرتے۔ اور نتیجتاً جہاں تک ہر سکتے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اگر ٹنڈے دل سے سرچا جائے تو اس طرح امریکہ کی جانب سے جنگ کے لئے مختلف ممالک میں بلا کس قائم کیے جارہے ہیں ویسے ہی اس کے ماہ مقابل پر لیگل فلاسفی (Political Philosophy) کو لیکر آگے بڑھنے والوں کے محاذ بھی قائم ہوتے جارہے ہیں۔ ایسٹ جرمنی سے لیکر چیکو سلواکیہ یا اس کے بعد ترکی۔ افغانستان یا گنگٹ کے جو امپائرلٹ سنٹرس ہیں اس پر کس کا قبضہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چائینا تبت کے بڑے دعوے دار کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ بہت بڑا سیاسی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے لئے امریکہ نے یہ بہتر سمجھا کہ پاکستان کو دھمکا دیا جائے۔ مجھے بڑی خدشی ہے کہ کم از کم ہندوستان کے سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مجھے اس پیکٹ سے ہندوستان کی آزادی اور امن کو جو خطرہ نظر آتا ہے وہ محض اس لئے نہیں کہ آئندہ آنے والی جنگ کی خاطر امریکہ پاکستان کو استعمال کریگا۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان بھی جنگ کی فک میں مبتلا ہو جائے۔ کئی آئیزن ہاور آسکتے ہیں جاسکتے ہیں ان کے وعدہ کاغذ پر رہ سکتے ہیں۔ لیکن نہ تو وہ کوریا میں کچھ کر سکتے نہ یہاں کچھ کر سکتے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ محض جنگ کو ہوا دے سکیں۔ میں کہوں گا کہ اس معاملہ میں پاکستان انوسنٹ (Innocent) نہیں ہے بلکہ اس نے بالارادہ اس اگر پیکٹ کو اپنایا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ نہ صرف کشمیر بلکہ کسی اور طویل پر ہندوستان کو جنگ زمانے میں آئینڈ کی شکل بنادے۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس پیکٹ سے جو ایک ایسے ملک پاکستان سے ہو رہا ہے جو ہندوستان کی بارڈر پر ہماری آزادی خطرہ میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس اصول پر ہنوزی نے پاکستان کے امریکی فوجی امداد کو لینے سے اتفاق نہیں کیا اسی اصول پر مجھے یقین ہے کہ اگر یوما یا رشینا میں بھی کوئی ایسا معاہدہ ہو تو پنڈت نہرو اس کی مخالفت کریں گے۔ لیکن اس صورت میں ہندوستان کو بڑی مشکل پیش آئیگی۔ لیکن یوما کی صورت میں شبہ ہے کہ گھر کے اندر کے بھیدی برابر اس کی تائید کرنے لگیں گے۔ اور ہندوستان انتہائی خطرناک صورت میں مبتلا ہو جائیگا۔ خدا نہ کرے کہ ایسی صورت آئے۔ لیکن متحہ محاذ کی باتیں ایسی باتیں ہیں جنہیں ہمارے ہندوستان کے بعض خاص سیاسی نظریہ رکھنے والے مانتے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ خود ہمارے لیڈر پنڈت نہرو اس معاملہ کی تعبیر نہیں کر سکتے اور اس قسم کا سیاسی مسلک رکھنے والوں سے کوئی متحدہ محاذ ہم نہیں بنا سکتے۔ یہ ہمارے اس پوٹر لیڈر کی رائے ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس پیکٹ کے پیچھے کئی باتیں انوالو (Involve) ہیں جو ڈیولپ ہونے والی ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ یہاں امریکہ کے پیکٹ کے سلسلے میں شبہ کیا گیا ہے کہ ممکن ہے اس سے ایک فرقہ واریت

فضاء پیدا ہو جائے۔ کیونکہ فرقہ واریت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے لیکن یہ سمجھنا کہ ایسے موقع پر ہندوستان کا کڑی مسلمان پاکستان کی تائید کرنا کہ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ چنانچہ متعدد موقعوں پر مسلمانوں نے یہ بتایا ہے کہ جب ہندوستان کی آزادی کا سوال آئیگا تو ہم اس کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ پیانے کے لئے بھی تیار ہیں۔ اس لئے میں کہوں گا کہ ہمیں فرقہ واریت کا اتنا ذرا نہیں سمجھنا کہ ہندوستان کی آزادی و امن کی راہ میں ہندوستان کے اندر کے اندر سے لڑ گئے ہیں جو ایسے خیالات رکھنے والے لوگ ہیں کہ.....

شری. جی. ڈی. دتتا:—مجھے اس چیز کا واضح کرنا ہے کہ میں اپنی تقریر میں مسلمانوں کی طرف کسی طرح کا خیال نہ کیا تھا۔ میرا خیال خاص کر ہندوستان سب سے زیادہ تھا جس کو ہماری سیکولر پالیسی پسند نہیں ہے اور جو ابھڑا ہوا ہندوستان ہے۔ میرا मतलब था कि जूनको जिस मौजू से अंतराष्ट्रीय मिलेगा और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान जमातों में फूट या मतभेद पैदा करने के लिये जिस मौजू का उपयोग करेंगे। मेरा कहने का यह कभी मंशा नहीं था कि यहां के मुसलमान पाकिस्तान की अन्नदात करेंगे।

شری لکشمی کونڈا:—بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کم از کم مسلمانوں پر تو اعتماد رکھتے ہیں۔ اور کسی ریزولوشن کے بغیر ان پر اعتماد رکھتے ہیں۔ لیکن ہندو سہا سہا کی کوئی قوت نہیں ہے۔ وہ کیا ایکسپلائیٹ کر سکتی ہے۔ ایکسپلائیٹ تو دوسری پارٹیاں کر سکتی ہیں۔ اس کی گنجائش ہے۔ ہندوستان ہی میں جو خطرہ ہے اس کو مجھے صاف الفاظ میں رکھنا ہے۔ پنڈت نہرو نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بیرونی ملک کی فوجی قوت کی بناء پر اپنی آزادی اور امن کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ یہی اس اصول کو سارے لوگ مانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی شکتی بہت بڑی ہے۔ اور وہ کسی قسم کے بھی حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے اس کا ضرور احساس ہے کہ ایسے حالات پیدا ہونے کے باوجود بھی آج ہندوستان کے کم سے کم بڑے سیاسی ادارے یا عوام کے نمائندے کہلائے جانے والے لوگ ایک پلیٹ فارم پر نہ آسکے۔ کیوں کہ ان میں ایک دوسرے پر اعتماد پیدا نہیں ہو سکا۔ میرا ہی بلکہ پنڈت نہرو کا بھی اعتماد پیدا نہیں ہو سکا جن کی تینوں میں آج ہم ایک کٹھن سمجھا کر حل کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ محض ہاشمنوں کے دوارا نہیں بلکہ عمل کے ذریعہ بتادیں کہ ہم خطرہ خواہ شمال مشرق سے آئے یا شمال مغرب سے کہیں سے بھی آئے ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور ہم گاندھی جی کے مارگ پر چل کر کریں گے۔ جمہوریت کی بڑی بڑی باتیں تو کی جاتی ہیں۔ لیکن جب دوسرا وقت آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی جمہوریت ہی نہیں ہے۔ کم از کم اس نوبت پر تو یہ تسلیم کیا گیا کہ ہندوستان جمہوری ملک ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ ایسی جمہوریت کی بناء پر ہم کسی بھی خطرہ کا مقابلہ اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ میں نے اصل ریزولوشن پر جو اسٹینٹس پیش کئے ہیں ان میں خاص اہمیت

رکھنے والی چند باتیں مضمیر ہیں۔ اصل ریزولوشن میں یہ دیا گیا ہے کہ اسکا امکان ہے کہ امریکہ دوسری جنگ کے لئے پاکستان کو اڈہ بنائے گا۔ میں عرض کرونگا کہ کیوں اسی حد تک رائے قائم کی جائے۔ یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ پاکستان خود اپنی طرف سے جنگ کریگا۔ جب کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ اس سے ہمارے ملک کی آزادی اس فوجی معاہدہ کی بناء پر برقرار رہے گی۔ پاکستان کیلئے اپنی آزادی اور امن کی خاطر معاہدہ کرنا ذرا بے معنی بات ہے۔ بلکہ یہ ان کا سوچا سمجھا ہوا منصوبہ ہے۔ اس کے لئے نہ صرف امریکہ بلکہ پاکستان بھی مساوی ذمہ دار ہے۔ اور یہ خطرہ ہندوستان کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ اس لئے میں نے ریزولوشن سے جو الفاظ ”محض امریکہ اڈے قائم کرے“ کے ہیں اس کو نکال دئے ہیں۔ تاکہ دونوں مساوی ذمہ داری کے ساتھ اس مسئلہ کو سوچیں۔ بلاشبہ ہم آج پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے پیرا گراف میں پہلے ہی محرک نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں لیکن ان دوستانہ تعلقات کے باوجود اپنی آزادی کی خاطر ”سیکیورٹی سیٹرس لینا پڑتا ہے تو کیا نہ لئے جائیں اس کے لئے ریزولوشن میں گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی گنجائش پیدا کی ہے۔ آزادی کی حفاظت اور امن کی خاطر حکومت جو مناسب کارروائی اختیار کر سکتی ہے عمل میں لائے۔ خواہ اس حفاظتی کارروائی میں ہمارے دوستانہ تعلقات پاکستان اور امریکہ سے بالکل ہی کیوں نہ ختم ہو جائیں۔ اگر ہماری آزادی ختم ہوتی ہے تو ہمیں ایسے تعلقات کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم کو آزادی اور امن کی ضرورت ہے۔ اسی مفہوم کو میں نے یہاں صاف الفاظ میں رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ محرک صاحب بھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس ترمیم کو مان لیں گے۔

اس کے علاوہ اصل ریزولوشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ”ملٹری الائنس ایکٹ اور الائنس میں بڑا فرق ہے۔ میں نے پاس ایسا کوئی مواد نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم الائنس سے ایسا پریزیمپشن (Presumption) یا رائے قائم کر سکتے ہیں۔ دونوں کاسٹری الائنس ہوگا۔ آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ امریکہ سے پاکستان کو فوجی امداد دی جائے گی۔ جو آگے ملٹری الائنس کی صورت اختیار کرے گی۔ یہی میں سمجھتا ہوں۔ اس لحاظ سے پہلے فقرہ کو میں نے تبدیل کر کے دوسرے الفاظ میں رکھا ہے اس کے لئے مجھے ترمیم پیش کرنی پڑی۔ ان حالات میں جو آج ملک کے سامنے ہیں ایسا معاہدہ جس سے یہ خاص صورت پیدا ہو تو نہ صرف اس ایوان سے بلکہ ہر جگہ سے اس بارے میں عوام کے صحیح جذبات دنیا پر ہتھیں ظاہر کرنا ہے۔ اور اس کے ذریعہ ہندوستان کے سارے عوام کو اس جانب توجہ دلائی ہے۔ یہاں سے باہر جانے کے بعد عملی طور پر ان کو لید (Lead) کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قرارداد کے محرک صاحب بھی ایسی کوئی صورت نکالیں گے جس سے باقی سیاسی پارٹیوں کے لوگ یا لیڈرس یا ورکرز کے دلوں میں ایک خاص سیاسی مسلک رکھنے والوں کے تعلق سے جو شبہ ہے وہ عملی طور پر دور ہو جائے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شبہات بہت ہی معقول قسم کے ہیں ۔ محض وہم پر مبنی نہیں ہیں ۔ جس طرح کہ امریکہ کے لائبریریز موجود ہیں کیا کام ہو رہا ہے ۔ کلچرل کام ہوتا ہے ۔ ان کا پیسہ بہتا ہے ۔ ویسے ہی دوسرے ممالک سے بھی ڈائریکٹری یا انڈائریکٹری ایجنٹس کے ذریعہ سے ایسے کا و بار یہاں پر جاری ہیں جس کو چک کرنے کی ضرورت ہے ۔ اس کو پنڈت نہو نے حال ہی میں پیپرو کی تقریر میں کہا ہے ۔ ہم ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے ۔ اگر فی الواقعہ اس پاک امریکن پیپاکٹ کی بنیاد پر وہ ہمارے تصفیہ سے بڑھ کر اندرونی طور پر کچھ کرنا چاہنے ہیں تو میں کہوں گا اور ہر زور الفاظ میں کہوں گا کہ وہ ملک کے ساتھ بڑی غامضی ہو گئی ۔ اگر فی الواقعہ پاک امریکن معاہدہ سے ایک بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے اور اس خطرہ کے لئے ہمیں تیار ہونا چاہئے تو اس معاہدہ کی جو اسپرٹ ہے جیسا کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک خاص قوت ہماری طرف بڑھ رہی ہے ۔ دنیا کا کوئی ملک بھی چاہے یہ قوت اختیار کرنا چاہے خواہ ہماری پڑوسی ملک کی جانب سے بھی یا خود ہمارے ملک کے اندر سے ایسی قوت استعمال کی جائے ہم ایک مضبوط محاذ قائم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں ۔ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں اس لئے اس جانب ترجیح کرنا بھی ہمارا فرض ہے ۔ میں امید کرتا ہوں کہ پنڈت جیواہر لعل نہو کی قیادت میں ایک طرف بغیر فاسیزم کے اثر میں آئے اور دوسری سامراجیت کی قوتوں کے چنگل میں پھنسے جس آزادی اور امن کے قیام کی طرف آج ہمارا ہونا بڑھ رہا ہے اگر سچ مچ آزادی کے خواہاں ہیں ۔ امن و امان کے خواہ ہیں تو ان کو بغیر کسی ریزرویشن کے پنڈت جی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا صرف اس مسئلہ کی حد تک اتفاق کیا گیا اور دوسرے مسائل میں اختلاف ہوتا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آج کے مسائل انٹر لنکڈ (Inter-linked) ہیں ۔ ایک مسئلہ کو ایک درستی سے اور دوسرے مسئلہ کی دوسری درستی سے نہیں دیکھا جاسکتا ۔ ہم آج کل یہ کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ کی تائید کریں اور دوسرے مسئلہ میں چارگالیاں دیدیں تو اس سے صحیح حالات امن اور آزادی کو برقرار رکھنے کیلئے پیدا نہیں ہو سکتے بلکہ یہ ہماری امن اور آزادی کے لئے ایک بڑا خطرہ ہوگا ۔ میں آج اس خطرہ کی طرف ایوان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ۔ اس کے پیچھے بھی میں آنریبل ممبرس کی درستی کو لیجنا چاہتا ہوں ۔ اس لحاظ سے ہمارے سامنے جو ریزولوشن ہے اس میں امن اسپرٹ کو پورا کرنے والے الفاظ ہاؤز کے سامنے ترمیم کی شکل میں پیش کیا ہوں ۔ اگر سچ مچ اس پیپاکٹ کے پیچھے جو اسپرٹ ہے جس کے اطراف و اکناف پھیلنے کا امکان باہر کے ممالک سے بڑھ کر اندر کے ایلیمنٹ (Element) سے ہے اور اس کو دور کرنے کے لئے سکیورٹی میژرس (Security Measures) لیتے ہیں تو وہ لوگ گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے اور یہ نہ کہا جائیگا کہ یہ بل نہو وہ بل نہ ہو ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سکیورٹی کے نام سے اتفاق سے بے گناہ زد میں آجائیں وہ پس جائیں لیکن ان کو گریٹر انٹرسٹ کے نام پر پسنا ہی چاہئے ۔ اس لحاظ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج مسائل پر سوچتے ہیں تو ایک مسئلہ پر ایک ڈھنگ سے نہ سوچیں

اور دوسرے مسئلہ پر دوسرے ڈننگ سے نہ سوچیں - بلکہ سارے مسائل کو مشترکہ طور پر سرجیں اور ڈیموکریٹک کنونشنس (Democratic conventions) کو آگے بڑھائیں - یہ رجحان ہے تو مجھے امید ہے کہ میری ترمیمات کو منظور صاحب خود تسلیم کر لیں گے - کیونکہ دنیا میں ہم کو ایک اہم ترین فرض انجام دینا ہے - امن اور آزادی کے فرض کو انجام دیکر ہمیشہ جمہوریت کا جھنڈا لہرانا ہے اس قدر کہتے ہوئے میں منظور صاحب سے پھر ایک بار اپیل کرونگا کہ وہ میری ترمیمات کو مان لیں -

श्री. अंकुशरात्र व्यंकटराव घारे :—अध्यक्ष महोदय, जो रेजोल्यूशन बहस के लिये आया है उसके ऊपर लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो अभी तकरीर हुई है वह काफी मसाल पर रोशनी डालती है। हम जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से जितने पैकट्स होते हैं वह उसकी अक्सपेन्स-निस्ट पालिसी की वजह से होते हैं। अतः यह पॉलिसी है कि अशिया के लोगों को अशिया के लोगों के साथ ही लड़ा कर अपना व्यापार बढ़ाना, यही पालिसी अतः कीरफ से कोरिया में भी अस्तित्पार की गयी थी। पाक-अमेरिकन पैकट उसी का अंक नमुना है। हमारी बदकिस्मती से कश्मीर का मसला अंक असा मसला है जिसकी वजह से अमेरिका को हिंदुस्तान में कोरिया का, रिपीटीशन करने के लिये अंक अच्छा बहाना मिल गया है। लेकिन यह जानना पड़ेगा कि अमेरिकन मदद आती है तो वह किसी के गले में जबर्दस्ती अतारी नहीं जा सकती। अगर कोयी मुल्क अमेरिकन मदद लेना नहीं चाहता तो अमेरिका बाम्बरो से उसको अिमदाद नहीं पहुंचाता। सही मानों में गलती है अतः लोगों की जो असा अंड अक्सेप्ट करते हैं। पंडित नेहरू ने यह बयान किया है कि हमारे दिल में यह बात कभी नहीं आयी कि पाकिस्तान की टेरीटरी पर हम अग्रेसन करें, और आज असा कोयी मुल्क नजर नहीं आता जो पाकिस्तान पर हमला कर सकेगा, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो नेचरल बैरियर्स हैं अतः देखते हुअे किसी को बाहर से खतरा नहीं दिखायी देता। अगर यह कहा जाय कि हिंदुस्तान से धोखा हो सकता है तो सारी दुनिया जानती है कि हमारी पालिसी कितनी साफ है, और हम किसी भी मुल्क पर अग्रेसन करने पर तुले हुअे नहीं हैं। फिर भी अिन सारे वाक्यात की रोशनी में यह पैकट किया गया है, और पाकिस्तान ने अपनी अित्सा-निबत को बेचकर, भीख मांग कर, अमेरिका की अिमदाद अपने मुल्क में लायी है। जैसे हमारे यहां अच. अी. अच. दि निजाम के वक्त रेसीडेन्ट रखा जाता था, और ब्रिटिश फौज रखी जाती थी और कहा जाता था कि वह निजाम के प्रोटेक्शन के लिये रखी गयी है। लेकिन दरअसल वह ब्रिटिशों की खुद की पावर प्रोटेक्शन के लिये रखी जाती थी। अिसी प्रकार पाकिस्तान में जो अमेरिकन मदद आयगी वह दरअसल अमेरिका के मूनाफे के लिये लायी जायगी। लेकिन अिमदाद देते हुअे आयसेन होवरने यह भी डिक्लेर किया था कि अिस अिमदाद का हम अग्रेसिव फुलपूज के लिये अुपयोग नहीं होने देगे। लेकिन ये सब बातें दोवार हजार मील की दूरीपर न्युयार्क में बेंचकर की जा रही हैं। अतः असर कुछ नहीं हो सकता। अगर कल अग्रेसन होगया, तो कल आयसेन-होवर यहां आकर उसको रोक नहीं सकते। अिसलिये जो अमेरिकन अंड ली गयी है, वह कश्मीर के मसले को हल करने के लिये ली गयी है। अब कश्मीर का मसला प्लेबिसाइट से हल होने वाला नहीं है। अिसलिये हमको कश्मीर के सवाल की तरफ अभी से लड़ायी के नुकतेनजर से देखना

पडेगा। हम चाहें या न चाहें दोचार साल के अंदर हम अेक लांग ड्रान वेंटरलमे घुसेंगे। जिसलिये हमको यह समझना चाहिये कि अपोजीशन पार्टी के लोग कहते हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू अेक सक्थूलर भेजते हैं कांग्रेस के लोगों को कि जिसके खिलाफ लोगों में राय कायम करना चाहिये वह की जाय तो उससे कुछ फायदा होनेवाला नहीं है। फिर जिस मसले को किस तरह से सोचना चाहिये। जिसको कम्युनल अप्रोच से बिल्कुल नहीं सोचना चाहिये। हम को जिस तरीके से सोचना चाहिये और तैयारी करनी चाहिये कि अगर हमारे अपर कोभी अग्रेसन करता है तो उसके दांत खट्टे बनजायें। जिसके लिये प्रैक्टिकल तरीका यह हो सकता है कि हमारे डिफेन्स की कूव्वतें पूरी तरह से मजबूत होने कि जरूरत है। भारत सरकार के डिफेन्स डिपार्टमेंट के डेप्युटी मिनिस्टर ने बजेट के डिसकशन का जवाब देते हुअे कहा था कि जिस मसले पर हम अच्छी तरह से सोच रहे हैं। और जिसके लिये सब डिपार्टमेंट्स को अच्छी तरह से आर्गनाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके पहले हमारे डिफेन्स मिनिस्टर श्री बलदेव सिंग ने कहा था कि टेरीटोरियल आर्मी या अेन. सी. सी. की तरह अेक लाइन ऑफ डिफेन्स कायम करनेवाले हैं। लेकिन आज तक हमारे मुल्क में जिस दृष्टि से कोभी प्रोग्रेस नहीं किया गया है। प्रैक्टिकल पाइंट ऑफ व्ह्यू से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आर्गनाइज करने के लिये हमारे यंग मैन को मिलिटरी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। जिसलिये स्कूल्स और कॉलेज्स के नौजवानों को कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग देना जरूरी है। बद किस्मती से हमारे नेताओं को सिर्फ तकिरें करने की आदत होगी है। लेकिन अनुकी मुंह की तोपों से यह अग्रेसन रूकनेवाला नहीं है। पार्लियामेंट जवाहरलाल नेहरू ने अेक तकरीर की थी कि जिस पॅक्ट की वजह से हमको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। बात सही है लेकिन जिस के बारे में हमको काम्प्लेसेंट भी रहने की जरूरत नहीं है। पंडित नेहरू को मैं कदर की नजर से देखता हूं, लेकिन अनुको प्लान्स बनाने की आदत हो गयी है। बड़े बड़े प्लान्स करने की अनुको आदत होगी है। और हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में सचमुच जो प्लान करी आउट करने की ताकत रखनेवाले व्यक्ति सरदार पटेल थे वे आज नहीं रहे हैं। मेरा कहना यही है कि प्रैक्टिकल नजर से जिस सवाल की तरफ देखने की जरूरत है। जिसलिये मैंने यह अमेंडमेंट पेश की है। शायद यह कहा जायगा कि जनरल मास सपोर्ट हासिल करने के लिये यह रेजोल्यूशन लाया गया है। जिससे हम जनरल सपोर्ट जरूर अेक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट के साथ साथ जिस बात पर भी हम अपना अटेन्शन फोकस करना चाहते हैं कि जिस वक्त हमारे देश को किस किस डायरेक्शन में ले जाना जरूरी है। जिसलिये मैंने यह अमेंडमेंट मुव्ह की है। हम देखते हैं कि आजकल हायस्कूल्स और कॉलेज्स में हमारे स्टूडेंट्स पढते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि डिसिप्लिन क्या चीज होती है। आज हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल डिअडिस्प्लिन्ड हैं। अनुमें सिर्फ डिसिप्लिन लाने के बहाने से नहीं लेकिन हमारे मुल्क का रिजर्व्वंड फोर्स बिल्ड अप करने के लिये ट्रेन्ड परसोनेल को किसी भी वक्त फराहम करने के लिये, और फिजीकल फिटनेस के अेक खास स्टेज पर अनुको लाने के लिये हमें अनुको मिलिटरी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। जिसके लिये जिस तरह से रेग्यूलर आर्मी के मॉटेनन्स के लिये खर्च किया जाता है उसी तरह से जिस ट्रेनिंग के लिये किया जाना चाहिये। जिसके लिये ट्यूटर्स रखने चाहिये। जिसके लिये हमें ज्यादा अेक्सपेंडीचर भी करना पडेगा, तो उसको हमें बर्दाश्त करना पडेगा। मैं आशा करता हूं कि मेरी अमेंडमेंट को हाउस तसलीम करेगा।

Shri Syed Akhtar Hussain rose in his seat....

مسٹر ڈپٹی اسپیکر۔ آپ پندرہ منٹ تقریر کیجئے تو مناسب ہے۔

شری سیاء اختر حسین (جنگاؤں) جناب اسپیکر صاحب۔ پندرہ منٹ بہت کم وقت ہے اگر اس مسئلہ پر مجھے کم از کم آدھا گھنٹہ تقریر کرنے کی اجازت دی جائے مناسب ہے۔

امریکہ اور پاکستان کا فوجی امداد کا باہمی معاہدہ آج اس ایوان میں زیر بحث آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہندوستان میں پارلیمنٹ کو چھوڑ کر یہ پہلی مثال ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس مثال سے پورے ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں کو نہ صرف ہم سبق دے سکتے ہیں بلکہ ان کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس قومی اہمیت کے سوال کو وہ بھی اٹھائیں اور ایک متحدہ آواز بلند کریں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اس مسئلہ پر اپنے خیالات کا اظہار کروں دو چار باتیں عرض کرنا ضروری ہے۔

آج سے چند ماہ پہلے کے حالات کی جانب میں اشارہ نہیں کروں گا۔ لیکن حال میں جو تبدیلی آئی ہے اور پنڈت جواہر لال نہرو نے جس طریقے اور جس ڈھنگ سے سوچنا شروع کیا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ پورے ملک میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب وقت آگیا ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام پارٹیاں مل کر ایک متحدہ محاذ بنائیں اور اس کیمپین (Campaign) کو آگے بڑھائیں۔ کانگریس نے اس سے قبل جو گشتیاں جاری کی ہیں ان کے متعلق ایوان کے سب نمائندے جانتے ہیں لیکن حال میں جو تبدیلی آئی ہے۔ جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دو تین روز قبل حیدرآباد پردیش کانگریس کے صدر شری کے۔ وی۔ رنگا ریڈی نے ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بلایا تھا کہ اس سوال پر غور کیا جائے اور ممکن ہو تو ایک متحدہ محاذ بنایا جائے۔ اس محفل میں اس سوال پر مختلف لوگوں کے مختلف نقاط نظر میں ایک ہم آہنگی محسوس ہو رہی تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس طریقہ سے کانگریس۔ اپوزیشن کی تمام پارٹیاں اور دوسری سیاسی۔ سماجی اور معاشی تنظیمیں مل کر اس قومی مسئلہ کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ابھی اس ایوان میں ایک آنریبل ممبر نے اس سوال پر جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ اتنی نیشنل خیالات ہیں بلکہ میں یہ کہنے پر تیار ہوں کہ اگر وہ اپنے ان ہی خیالات کو ان ہی محسوسات کو ان ہی نظریوں کو ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس بھیجیں تو وہ بھی اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ ہندوستان کی موجودہ خارجی پالیسی جو اس کے سلسلہ میں ہے اس کے خلاف پڑتے ہیں اور پاکستان۔ امریکن پیکٹ کے سلسلہ میں بھی جو پالیسی ہندوستان سرکار کی ہے اس کے خلاف پڑتے ہیں۔ کیونکہ پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ صاف صاف کہا اور دوسری

پارٹیوں نے بھی انہیں یہ یقین دلایا ہے کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے اس پر متحدہ طور پر آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں کسی پارٹی یا کسی الگ سیاسی نقطہ نظر کا تصور نہیں آسکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی سامنے رکھی گئی ہے کہ بہت سی پارٹیاں اور لوگ اس مسئلہ کو ایکسپلاٹ کریں گے۔ یہ جو اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے وہ تو پنڈت جواہر لال نہرو کے ذہن میں بھی موجود نہیں ہے جس کا اشارہ ابھی میرے محترم دوست نے کیا ہے۔ میں اس آنریبل ایوان کے سامنے صاف الفاظ میں یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ پچھلی بڑی لڑائی کے بعد جو تبدیلیاں آئیں اور پچھلے چھ سات سال کے دوران میں ہندوستان کی جو خارجی پالیسی رہی اور ہندوستان کی مختلف سیاسی جماعتوں نے جس طریقہ سے ہندوستان کی امن اور جمہوریت کی خارجی پالیسی کی تائید کی اس کے بعد پھر اس طریقہ سے ان پارٹیوں کے متعلق شکوک اور بے اعتدائی ظاہر کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کانگریس کے اندر آج بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو وسیع نقطے نظر سے نہیں سوچنا چاہتے۔ اور آج اس مسئلہ کو اتنی اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں ہیں جتنی اہمیت کا مستحق وہ مسئلہ ہے اس کو دوسرے ڈائورشن میں لیجانا چاہتے ہیں۔ وہ وہی سمت ہے جس کی جانب امریکی سامراج آج ہندوستان کو لیجانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایسے عناصر باقی رہیں جو اس مسئلہ کو اس طریقہ سے پیش کر کے آپس میں بھوٹ پیدا کرنے کوشش کریں۔ اور رجعت پسند اور فرقہ پرست عناصر کو حاوی رکھیں اور ایسی فضا پیدا کریں جس کے تحت پنڈت نہرو کی پالیسی کو ناکام بنایا جائے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان ہی احساسات کو۔ ان ہی نظریات کو لیکر چلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاکہ امریکی سامراج اس سازش میں کامیاب ہو جائے اور اگر کامیاب نہ بھی ہو تو کم از کم اس کو تقویت تو حاصل ہو جائے۔ اس لئے میں ان ترمیمات کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے آنریبل دوست سے یہ عرض کروں گا کہ وہ اپنی ترمیمات کو واپس لے لیں چونکہ وہ خود ہندوستان کی خارجی پالیسی اور پنڈت نہرو کے منشاء کے خلاف ہیں اور اس وقت ہمارے سامنے جو سوال ہے اس کو نظر انداز کرنے کے برابر ہے۔ یہ خیالات ایسے خطرناک رجحان کا پتہ دیتے ہیں جس سے ہمارے ملک کے بڑھتے ہوئے اتحاد کیلئے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نقطے نظر اور اس رجحان کو چھوڑنا ضروری ہے۔

اس کے بعد میں ایوان کے سامنے پس منظر کے طور پر چند بین الاقوامی حالات کی جانب اشارہ کروں گا۔ اس لئے کہ جب تک اون کو نہ سمجھا جائے اس مسئلہ کے خدوخال کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی۔ پچھلی بڑی لڑائی کے بعد سے دنیا کے اندر ایک بڑی سامراجی طاقت کی حیثیت سے امریکہ کا حکمران طبقہ سامنے آیا ہے۔ اس نے پچھلے آٹھ نو سال میں ساری دنیا میں اپنے فوجی اڈے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مشرق بعید میں۔ مشرق وسطیٰ میں۔ یورپ اور مغربی ممالک میں اور خود برطانیہ میں (اوس پر اپنے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے دباؤ ڈال کر) فوجی اڈے قائم کئے۔ یہ عمل

خود اوس کے ارادوں کی دلیل ہے اور اوس سے حقیقتاً کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا۔ میں اس سلسلہ میں خود ایک امریکی اخبار کے اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ’’یو۔ یس۔ نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ‘‘ نے اپنی ۲۵۔ دسمبر سنہ ۱۹۵۳ء کی اشاعت میں ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں اوس نے بتایا ہے کہ آج کمیونسٹ ممالک کو چھوڑ کر دنیا کے ۶۳ ملکوں کی سر زمین پر امریکہ کے فوجی اڈے قائم ہیں۔ یہ حقیقت اوسے اخبار کی زبان سے ہم سن رہے ہیں جو وہاں کا ایک نیم سرکاری اخبار سمجھا جاتا ہے۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ ان اڈوں پر دس لاکھ امریکی سپاہی۔ اور دوسرے امریکی مبصرین اور اکسپرٹس کی حیثیت سے موجود ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ پچھلی لڑائی کے وقت ان اڈوں کی تعداد (۳۵) تھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ امریکہ کی اگریسیو پالیسی اور جارحانہ اقدام مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ چند سالوں کے اندر ہی اوس نے صرف اپنے فوجی اڈوں کا جال اس قدر پھیلا دیا بلکہ دنیا کے آزاد اور جمہوری ممالک کو بھی اپنے گھیرے میں لیتا جا رہا ہے تاکہ اپنی جنگی معیشت برقرار رکھی جاسکے۔ اپنی منڈیاں بڑھائی جاسکیں۔ اپنے کاروبار اور منافع کو بڑھایا جاسکے۔ اپنے تسلط کو برقرار رکھا جائے اور اوس کو تقویت پہنچائی جائے۔ وہ تیسری عالمی جنگ شروع کر کے جنگی فضا کو باقی رکھ کر اپنے ناپاک منصوبوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی گوشہ سے بھی یہ کہا جائے کہ سوویت روس جنگ چاہتا ہے یا چین جنگ چاہتا ہے تو وہ غلط ہے۔ فاشیسم اور امپریلسٹ طاقتیں ہی اس کی گنہگار ہیں ہندوستان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اور کانگریس کے اندر بھی جو ایماندار عناصر اور دوسری پارٹیوں کے لوگ اور ساری دنیا کے آزادی پسند اور امن پسند دوست لوگوں کی زبان سے کبھی ہمارے یہ سننے میں نہیں آیا کہ سوویت روس یا چین جنگ چاہتے ہیں۔ پنڈت سندھ لال جی۔ جے۔ سی کمار اپا، سیف الدین کچلو اور دوسرے بہت سارے لوگ جو پچھلے چند سالوں میں روس اور چائنا ہو آئے ہیں انہوں نے صاف صاف الفاظ میں کہا ہے کہ روس میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ملیگا جو جنگ چاہتا ہو۔ وہ لوگ امن کے خواہاں ہیں۔ وہ ملک اپنے تعمیری کاموں میں مصروف ہے۔ یہی حال چین کا بھی ہے۔ معقول طور پر بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ کیوں کہ پچھلی بڑی لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان سوویت روس نے اٹھایا ہے۔ اب وہاں کے لوگ اپنے ملک کی نئی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اوس ڈھانچے کو جو ٹوٹ گیا ہے۔ جو شکست ہو گیا ہے بنانے میں مصروف ہیں وہ لوگ کس طرح جنگ کے متعلق سوچ بھی سکتے ہیں۔

اس کے متعلق نظریاتی بحث بھی کی جائے تو اس کے ثبوت میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اگر ہم حالات کا جائزہ لیں اور دنیا کے نقشہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ چین اور روس میں جنگی حالات نظر نہیں آتے۔ اس کے برخلاف امریکہ نے خود وہاں کے اخبار کے بیان کے مطابق دنیا کے ۶۳ ممالک میں اپنے فوجی اڈے قائم کئے ہیں۔ دوسری بڑی لڑائی میں جن ملکوں کو غلام بنایا گیا وہاں فوجی اڈے

قائم کئے۔ - مشرق کے بعض ملکوں میں بھی یہی حال ہے۔ جاپان سے امریکہ نے حال ہی میں فوجی معاہدہ کیا ہے اور وہاں بھی فوجی اڈے قائم کئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایشیا کے اندر امریکہ کے کیا منصوبے ہیں۔ فاروسا میں چپانگ کاٹی شیک کو باقی رکھ کر جس طرح سے اس کی مدد کی جا رہی ہے یہ اس کی دوسری دلیل ہے۔ اسی طرح مشرق بعید کے دوسرے ملکوں کو جس طرح سے امریکہ کی مدد مل رہی ہے اس کے بارے میں تمام لوگ جانتے ہیں۔ اخباروں میں روزانہ خبریں آتی ہیں۔ حال ہی کا واقعہ ہے کہ امریکہ کے بمبار ہوائی جہاز انڈوچینا کی لڑائی میں مصروف دیکھے گئے۔ پنڈت نہرو چاہتے ہیں کہ انڈوچینا کے اندر امن قائم ہو اور وہاں جنگ بند ہو جائے لیکن دوسری طرف امریکی فوجی بمبار وہاں اپنی کاررائیوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے مشرق بعید اور مشرق وسطیٰ میں اور خود برطانیہ میں بھی جو امریکی سامراج کا چھوٹا بھائی ہے اس کے فوجی اڈے قائم ہیں برطانیہ کے جہاں جہاں اثرات تھے وہاں سے اس کو نکال کر خود اپنا تسلط قائم کر رہا ہے۔ ترکی کے ساتھ جس طرح اس نے فوجی معاہدہ کیا۔ مصر میں جس طرح گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ایران میں جس طرح ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا یہ سب چیزیں اس کے جارحانہ عزائم کی دلیل ہیں۔ ان ممالک کے بعد اب پاکستان میں وہ آ رہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کا فوجی معاہدہ ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے کونسی کوشش کام کر رہی ہے۔ امریکی سامراج کی جانب سے اون ملکوں کے خلاف جن کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں ایک گھیرا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب ہم اس واقعہ پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کوشش کے خدوخال صاف صاف نظر آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی سرحد ایک طرف سویت روس اور دوسری طرف ہندوستان سے ملی ہوئی ہیں۔ اس موقف سے فائدہ اٹھا کر امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ واشنگٹن سے لاہور تک ایک ایسا خط کھینچا جائے کہ جنگ کی صورت میں روس اور چین پر بمباری کی جاسکے۔ چونکہ ہندوستانی عوام۔ ہندوستانی حکومت امریکہ کے آگے جھکنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ امریکہ کی غلامی کو وہ قبول نہیں کرتے اس لئے اس پر اس طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ رجعت پسند اور فرقہ پرست عناصر جو اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کے سیاسی پارٹیاں اس کو اکسپلاٹ کرینگے۔ اور اندرونی طور پر بغاوت پیدا کر کے یہاں کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ہندوستان میں اپنا تسلط قائم کرینگے۔ ہندوستان سے قریب اور اس کی سرحدوں سے ملے ہوئے جو دوسرے ممالک مثلاً۔ سیلون انڈوچینا۔ سلاوا وغیرہ ہیں اون پر مغربی سامراج کا تسلط پہلے سے ہی قائم ہے۔ اس سامراج کے خلاف جب ایک متحدہ محاذ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس قسم کے اندیشے اور شبہات پیش کئے جاتے ہیں جس طرح سے کہ ابھی پیش کئے گئے ہیں۔ ایک متحدہ محاذ بنا کر جب اس خطرناک طاقت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کی باتیں بعض گوشوں

سے کی جارہی ہیں۔ لیکن اس قسم کی باتیں آج کامیاب نہیں ہوسکتیں۔ ہندوستان کی بیدار جنتا اور ہندوستان کی بیدار قیادت اس قسم کی باتوں کو قبول نہیں کرسکتی۔

پنڈت جواہر لعل نہرو نے پاک امریکی معاہدہ کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اس سلسلے میں جو تقریریں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر انہوں نے کی ہیں انکا ہندوستان کے ہر گوشے میں خیر مقدم کیا گیا ہے۔ سوویت روس اور چین پر امریکہ کی طرف سے جو ڈورے ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ کی آگ کو امریکہ بھڑکانا چاہتا ہے۔ اس بارے میں ہندوستان کے عوام پنڈت جواہر لعل نہرو کی پالیسی سے بالکل متفق ہیں۔ یہی نہیں بلکہ سوویت روس کے وزیراعظم نے بھی پنڈت جواہر لعل نہرو کی پالیسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پنڈت نہرو اس کی خاطر بہت بڑا پارٹ پلے (Part play) کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ ممالک ہیں جو اس پسند ممالک کے ساتھ دینے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف کچھ اس قسم کی باتیں کی جارہی ہیں جن سے اون پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ اس موقع پر میں اس مسئلہ کے دو ایک پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرونگا۔ اس لئے کہ وقت کم ہے۔ اس مختصر سے وقت میں مسائل کے پورے پھلاؤ کو سمیٹا نہیں جاسکتا۔ یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کس طرح کے رہینگے۔ میں واضح لفظوں میں صاف طور پر اعلان کرونگا کہ ہندوستان کے عوام ہندوستان کے جمہور پسند طبقات پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی خوشحالی اور سلامتی کے خلاف نہیں ہیں۔ اس چھوٹے سے نازک فرق کو ہمیں محسوس کرنا چاہئے کہ ہمارے احتجاج کا رخ پاکستانیوں کی طرف نہیں بلکہ پاکستان کے اون حکمرانوں کے خلاف ہے جو امریکی سازش میں پھنس گئے ہیں اور اس کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ہمارے تعلقات ترقی کریں ثقافتی معاشی اور تجارتی تعلقات ترقی کریں خود پاکستان کے عوام اس امریکی امداد کے خلاف ہیں۔ ان کے احتجاج کی آواز کہیں کمزور اور کہیں طاقتور ہے۔ میں مغربی پاکستان کے بعض اخبارات کا ذکر کرونگا۔ امروز اور پاکستان ٹائمز (Pakistan Times) جو وہاں کے طاقتور اخبارات ہیں۔ (Bell rung) میں نے درخواست کی تھی کہ مجھے کچھ زیادہ وقت دیا جائے اور یہ سمجھکر کہ میری درخواست قبول کی گئی اپنی تقریر کو اس لحاظ سے آگے بڑھا رہا ہوں۔

مسٹر ڈپٹی اسپیکر - (۳۰) منٹ ہونے کے لئے (۳) منٹ باقی ہیں۔

سید اختر حسین - میں عرض کروں گا کہ پاکستان میں بھی اس معاہدہ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ مغربی پاکستان میں کم ہو رہا ہے اور مشرقی پاکستان میں زیادہ۔ ہندوستان اور پاکستان کے عوام کا احتجاج اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں اپنے ہمسایہ ملکوں

کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور امن قائم رکھنے کی جادو جہد کر رہے ہیں۔ اور اس معاہدہ کے خطرناک اثرات کا احساس رکھتے ہیں۔ آیزن ہور نے صدارت کی کرسی پر آنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ ایشیاء والوں کو ایشیاء والوں سے لڑاؤ۔ امریکی سامراج ایشیاء کی سرحدوں پر جنگ کی آگ بھڑکا کر یہاں کے لوگوں کو ایندھن کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے۔

ان خطرناک مقاصد کو عوام پیش نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں متحدہ طور پر آگے بڑھ کر اس سازش کے تختہ کو الٹ دینا چاہئے۔ اور اگر ہم متحدہ طور پر آگے بڑھیں تو اس سازش کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ صرف یہ کہہ کر ہم خاموش ہو جائیں کہ پنڈت جواہر لعل نہرو اس سازش کو ناکام بنانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں تو یہ مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم پورے ملک کو اس مسئلہ پر متحد نہ کر سکیں تو صرف پنڈت جواہر لعل نہرو کے احتجاج سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ سرد خنگ ہندوستان کی سرحدوں پر آگئی ہے۔ ہندوستان میں بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہاں امریکس ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں۔ ہمارے کیمپوں میں ہمارے کارخانوں میں ہمارے بازاروں میں اور ہمارے دفاتروں میں ٹیکنیکل ڈوائیزس کی صورت میں اور مختلف روپ میں اخبارات کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ وہ اپنے فلموں کے ذریعہ اپنی کتابوں اور لائبریریوں کے ذریعہ اور دوسرے ذرائع اور اپنی مشینز کے ذریعہ کمیونزم کے خلاف اور پنڈت جواہر لعل نہرو کی پالیسی کے خلاف عوام کو ابھار رہے ہیں اور پروپیگنڈہ کر رہے ہیں۔ یہ نہایت خطرناک چیز ہے۔ اور ہمارا داخلی اور گھریلو خطرہ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے انسداد کیلئے متحدہ طور پر آگے بڑھنا چاہئے۔ لیکن یہ ہمارا متحدہ محاذ پاکستان کے خلاف نہیں ہوگا۔ پاکستان کے عوام کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کے اُن حکمرانوں کے خلاف ہے جو امریکی جال میں پھنس گئے ہیں اور پورے مشرق بعید کو اس جال میں گرفتار کر رہے ہیں۔ میں ایوان سے اپیل کروں گا کہ اس اہم مسئلہ پر تنگ نظری کے ساتھ نہ سوچا جائے اگر ایسا کیا گیا اور اسکو وسیع حدود میں لا کر دیکھنے کی کوشش نہ کی گئی جیسا کہ سوچئے جانے کی وہ مستحق ہے اور پنڈت جواہر لعل نہرو کی پالیسی ہمارے پیش نظر نہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال پر جس اہمیت کے ساتھ غور کیا جانا چاہئے نہ کر سکیں گے۔ اگر ہم خوابوں کی تعبیر میں الجھ جائیں اور آنے والے اندیشوں کو نظر انداز کر دیں تو یہ ہمارے لئے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ چاہئے کہ کانگریس پارٹی متحدہ طریقہ پر کمپین (Campaign) چلائے اور سب ایک نقطہ پر متحد ہو جائیں اور اس میں انتشار آنے نہ پائے اور کسی گوشے سے انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو ہم ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں چند اقتباسات ہاؤز کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت کم ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ

دوسرے لوگ اس مسئلہ کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔۔۔۔۔

شری. بھئی. ڈی. دیشپانڈے :—میں نے آپ سے اپیل کرنا ہے کہ تقریباً ۱۰ لوگوں کی جانبداری سے ریزولوشن ہاؤس کے سامنے آیا ہے، اور ابھی جنہوں نے تقریر کی ہے وہ اس میں سے ایک ہیں۔ ان کو اپنے خیالات کو رکھنے کا موقع دیا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ ریزولوشن آج ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگلے نائن-آفیشیال ڈے پر بھی یہ چلنے والا ہے۔ اس لیے جنہوں نے ریزولوشن رکھا ہے ان کو زیادہ وقت دیا جائے۔ حالانکہ ممبران کا خیال رکھیں گے۔

مسٹر ڈپٹی اسپیکر۔ جملہ ۱۰ محرکین ہیں۔ ان سب کے لئے وقت دیا جائے تو دقت ہوگی۔

شری. بھئی. ڈی. دیشپانڈے :—لیکن سب ممبران آدھے گھنٹے تک تقریر کرنے والے نہیں ہوں گے۔
مسٹر ڈپٹی اسپیکر۔ جو جو محرکین تقریر فرمانا چاہیں انہیں کافی وقت نہ دیا جائے تو ڈسکشن کی اسپرٹ فوت ہو جائیگی۔

Shri V. B. Raju : Mr. Speaker, Sir, I would like to submit that the Leader of the Opposition and the Leader of the House should hereafter try to draw up a panel of names of Speakers from both sides, so that there may not be a confusion like this. The Mover of the resolution himself has, in my opinion, taken about 40 minutes, and if the Members of the Opposition themselves want to speak all the day, the Members on this side will not have an opportunity to speak at all. Let us try to fix the time-limit of 15 minutes for each Member and try to complete the speech.

The Chief Minister (Shri B. Ramkrishna Rao) : I would like to suggest, Sir, that this is a very important matter and I am sure hon. Members on both sides will have a desire to speak and express their views. I would request you to give them consideration and allow them to speak, of course fixing the time-limit. I understand that on this side of the House there are a number of Members who want to speak on this resolution. I feel that probably on the other side also there will be a number of Members who will be wanting to speak. I have absolutely no objection if you give them enough time to express their views.

Mr. Deputy Speaker : I think, if many members desire to speak, it is better to fix the time limit at 15 minutes and not more than that.

श्री. नरेंद्र (कारवान) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मुआहदे के संबंध में हाउस के सामने आया है उसके जरिये से हैदराबाद की तारीख में और हैदराबाद की असेंबली की तारीख में यह पहला मौका हमने बहाल किया है जिसके अपूर हम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों के बारे में अपने खियालात का अिजहार कर सकते हैं। मुझे इस सवाल की तरफ देखने से वह कहावत याद आती है कि तारीख अपने को दोहराती है और यह मसला भी उसी मानों में बिल्कुल सहीं मालूम होता है। मुगल बादशाहों के जमाने में जहांगीर ने एक बड़ी तारीखी गलती की थी और वह यह थी कि ब्रिटिश लोगोंको अन्होंने हिंदुस्तान में तिजारत करने का मौका दिया। आज पाकिस्तान दूसरी एक बहुत बड़ी गलती दोहरा रहा है कि वह अशिया के अंदर अमेरिका को फौजी अड्डा दे रहा है। अखबारात में इस मुआहदे के बारे में जो खबरें आती हैं उनसे मालूम होता है कि यह दूसरी गलती दुयनिया की तारीक में हो रही है कि अशिया के अंदर साम्राजियत को आगे बढ़ने के लिये मौका दिया जा रहा है। इस सवाल की तरफ देखने से बहुत सारी पुरानी बातें याद आती हैं। आप सब पर यह बाजे हैं कि १९१४ के पहले जंग के मौके पर आम तौर पर अमेरिका की पालिसी तिजारती पालिसी रही। उसका यहीं मकसद रहा कि दुनिया के मार्केटों में अपने कारखाने में बनायी हुयी चीजें फराहम करें और सरमाया जमा करें। इस तरह अमेरिका ने उस वक्त लाडाओ में अपने आपको शरीक नहीं किया, और इस पॉलिसी को लेकर पहले जंग के मौके पर उसने बिल्कुल अलहदा रहना मुनासिब समझा। उसमें तमाम दुनिया के अंदर अपने कारखानोंसे बनने वाली हथियार सप्लाय कर के दुनिया की लडाओ को अपने आंखों से देखते हुये अपने मुल्क को दौलत से मालामाल बनाने की पालिसी अख्तियार की, लेकिन हालात बदलने लगे, जमाने ने करवट बदली, दो भिन्न विचार-धाराओं दुनियाके अंदर काम करने लगीं तो उसका नतीजा यह हुआ कि दूसरी बड़ी लडाओ हमारे सामने आयी। मैं समझता हूं कि दूसरी लडाओ दो खियालात की टक्कर थी। साम्राजियत और डिक्टेटरशिप (Dictatorship) के दरमियान की -वह एक बहुत बड़ी लडाओ थी। उसमें साम्राजियत ने डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया, लेकिन उस वक्त एक अब्बाम का मुत्तहिदा महाज कायम हुआ। दुनिया के लोगों ने महसूस किया कि अगर हम सब मुत्तफिक होकर डिक्टेटरशिप का मुकाबला नहीं करते तो बहुत मुमकिन था कि सारी दुनिया में हिटलर का फैसीजम (Fascism) और उसका राज कायम होजाता और अन्सानियत और जमहूरियत का जो एक गहरा ताल्लुक है वह खतम होजाता। इस मौके पर अमेरिका एक साम्राजियत के तौर पर उनमें शामिल हुआ और उसने हिटलर के जंग का मुकाबला किया। उसके बाद से अमेरिका की दुनिया के अंदर जो कोशिशें रही उनकी तरफ सिर्फ अिशारा कर देना मैं इस वक्त जरूरी समझता हूं। जब लडाओ यूरोप से निकलकर अशिया की तरफ बढ़ी तो जापानी फौजें रंगून तक आकर पहुँची, और इस तरह से डिक्टेटरशिप ने एक बहुत बड़े अिलाके पर अपना अख्तियार जमा लिया तो उसका नतीजा यह निकला कि रूस, अमेरिका, अंग्लंड और फ्रान्स की फौजें दुनिया में कुछ जर्मनी की तरफ और कुछ अशिया की तरफ इस तरह से बंट गयीं। नतीजतन जापान को अशिया में हार खानी पड़ी और वह खास तौर से अमेरिका की वजह से। तब से लेकर आज तक अमेरिका ने अशिया के अंदर अपने सिंघासी मकसदों को पूरा करने के लिये अनेक चालबाजियां कीं। जापान उस वक्त दो हिस्सों में बांटा गया। जापान के अंदर उसने

काफी कोशिश की। जापान आखिर उसके कब्जे से निकल गया है। कोरिया का भी वही हाल हुआ। जिस तरह से अमेरिका का जो अि़रादा था कि अेशिया में अपना अड्डा कायम करे वह पूरी तरह से सफल न हो सका। अमेरिका का मुकाबला करनेवाली दूसरी कुवत दुनिया में रूस की थी जो चाहती थी कि अपनी विचारधारा का अेशिया के अंदर फैलाव हो। मैं यह कहन चाहता था कि पाकिस्तान और अमेरिका का यह जो मुआहदा है, वह अमेरिका की अेशिया में अपने फौजी अड्डे बनाने की कोशिश का एक जुज है। अिन खियालात की ताअीद वजीरे आजम पाकिस्तान के अुस बयान से होती है जो अुन्होंने कलकत्ते के डमडम हवाअी अड्डे पर लकाके वजीरे आजम से मुलाकात के वक्त अखबारवालो के सामने दिया था। अुन्होंने कहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो मुआहदा हो रहा है वह तीन बातों को सामने रखकर किया जा रहा है। सब से पहली बात कश्मीर का मसला है, दूसरी बात हमारी हिफाजत का सवाल है और तीसरी बात अशिया में बढ़ती हुअी कम्युनिस्टों की ताकत है। अिन बातों को पेशेनजर रखते हुअे पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मुआहदा करना जरूरी समझा। मैं अिस मुआहदे को दो गरजमदों के बीच का मुआहदा समझता हूं। एक तरफ अमेरिका को अेशिया के अंदर कदम जमाने के लिये जगह चाहिये और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो मआशी ढांचा बुरी तरह अुखड चुका है, अुसको पाकिस्तान सभालना चाहता है। पाकिस्तान की अेख्तदार सियासी जमाअत मुस्लिम लीग जो आज कराची में अपना अेख्तियार जमाय हुअ है वह मशरीकी पाकिस्तान के अंदर मार खा चुकी है। मशरीकी पाकिस्तान के अंदर जो अभी चुनाव लडे गये वे अिसी बुनियाद पर लडे गये कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मुआहदा किया जाय या न किया जाय।

Shri B. D. Deshmukh (Chairman) in the Chair

मशरीकी पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के खिलाफ वहां की अव्वाम ने एक युनायटेड फ्रंट कायम किया। अुसका यही नारा था कि यह मुआहदा अेशिया की आजादी और अेशिया की अव्वाम के लिये खतरा है और अिनसानियत को बहुत बुरी तरहसे नीचे गिरानेवाला है। अिन्ही जजबात को लेकर मशरीकी पाकिस्तान की अव्वाम ने अिलेक्शन की लडाअी लडी और अुसने कराची की बरसरे अेखतेदार पार्टी के लोगों की आंखे खोल दी। अुन्होंने बताया कि अिस मुआहदे के खिलाफ स्वयं पाकिस्तान की जनता है। मेरे कहने का मंशा यह था की अमेरिका ने अपने एक खास सियासी मकसद को लेकर अेशिया में आगे बढ़ने की कोशिश की है और जापान के अंदर जब अुसको पूरी शिकस्त हुअी तो अुसने चायना के अंदर भी अपने कदम बढ़ाये। अभी अभी एक ऑनरेबल मॅबर ने अखबारात से कुछ आंकडे पेश करते हुअे बताया कि लडाअी के पहले, दरमियान में और बाद में अमेरिका के दुनिया में कितने अड्डे हैं, अुसी तरह से मैं हवाला देकर बतला सकता हूं कि दुनिया की दूसरी जंग खतम होने के बाद चायना की सरकार को जो अुस वक्त एक नेशनलिस्ट सरकार कहलाती थी, अुसको ८० करोड डालर की मदद दी गयी। ८० करोड डालर के हथियार अुस वक्त की चीनी सरकार को अमेरिकाने सप्लाय किये थे और वह भी अिसी अि़रादे से कि अुन हथियारों के बल पर चायना जैसे अेशिया की बहुत बडी ताकत पर वह कब्जा हासिल कर सकेंगे। चीन जो अेशिया का दरवाजा कहलाता है अुसको हासिल करके हम आसानी से अेशिया में अपने पैर फैला सकेंगे। मगर वहां के बदलते हुअे हालात और वहां की अव्वाम के अिज़्जत चाहते हैं वह किसी भी पार्टी के हों, कोअी भी गवर्नमेंट अुन्होंने वहां कायम की हो अुससे हमें

यहां पर बहस नहीं है लेकिन यह कहने पर मैं अपने आपको मजबूर हूँ कि अमेरिका के हथियार खुद अमेरिका के मौत के लिये कारण हुए और आखिर में चायना से उनके पैर पूरी तरह से अखंड गये। उसके बाद अमेरिका की सियासी पार्टियों ने समझा कि अंक बहुत बड़ा मुल्क हमारे हाथ से निकल गया। अब हमें अशिया के दूसरे किसी मुल्क में कोशिश करनी चाहिये और अपने को मजबूत बनाना चाहिये। इस दृष्टि से उन्होंने दूसरी कोशिश हिंदुस्तान में करनी चाहि। उस वक्त मुझे उस जमाने की याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जब हिंदुस्तान में अजनास की हालत बहुत खराब थी और हमें दूसरे मुल्कों से अनाज लाना पड़ता था वह भी इसी अिरादे से कि चाहे रुपया कितना ही लगे लेकिन हम अपने मुल्क के किसी आदमी को अनाज की कमी की वजह से मरने नहीं देंगे। फिर चाहे हमारी तरक्की रुक जाय, यह जो हम में जजबात थे उनकी वजह से हमें अमेरिका से अनाज मंगवाना पडा। उस वक्त अमेरिका ने गेहूं वगैरा अनाज देने के बारे में कुछ पाबंदियां आयद करने की कोशिश की, उस सिलसिले में पार्लिमेंट में तकरीर करते हुये हिंदुस्तान के वजीरे आजम पंडित जवहरलाल नेहरू ने पाबंदियों के साथ इस तरह की अनाज की अिमदाद को लेने से अिन्कार किया। उन्होंने कहा कि पाबंदियों के साथ रोटी खाकर जिंदा रहने के बजाय बिना रोटी के हिंदुस्तान में अगर आदमी मरते हैं तो मैं उन्हें मरते हुअे देखना ही पसंद करूंगा, लेकिन पाबंदियों की रोटी खाकर गुलामी की जिंदगी बसर करना न मैं खुद चाहता हूँ और न मेरा मुल्क चाहता है। हिंदुस्तान की पूरी अव्वाम के जजबात की यह तकरीर अंक नजीर थी। उस वक्त अमेरिका ने समझा कि इस तरह से हिंदुस्तान पर पाबंदियां डालने से काम चलने वाला नहीं है तो उन्होंने दूसरी चाल चली। हिंदुस्तान के वजीरे आजम पंडित नेहरू को अमेरिका बुलाकर उनका शानदार अिस्तकबाल किया। चमकीले और रंगीले तरीकों से अपनी सियासी चालों के अंदर हिंदुस्तान के वजीरे आजम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की लेकिन उसमें भी वह नाकामयाब हुअे। यह अमेरिका के लिये दूसरी नाकामयाबी थी। उसकी तीसरी नाकामयाबी कश्मीर के अंदर हुअी। कश्मीर जिस वक्त दो हिस्सों में बांटा गया है और वहां क्या चल रहा है वह आप सब पर वाजे है। कश्मीर में उन्होंने बहुत धुम मचायी। दो तीन महीने पहले मुझे कश्मीर जाने का मौका हुआ था। वहां की बरसरे अेख्तेदार पार्टी के अच्छे से अच्छे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने वहां इस बात की कोशिश की थी कि कश्मीर की अव्वाम में हिंदुस्तान के खिलाफ किसी तरह से जजबात पैदा कर के कश्मीर के लोग आजाद रहें और अपना अंक अलाहिदा स्टेट बनायें। उस वक्त के कश्मीर के वजीरे आजम शेख अब्दुल्ला के साथ उन्होंने अपने संबंध प्रस्थापित किये और उनके साथ इस तरह का अंक मुआहदा तकमील पानवाला ही था कि वह राजफाश हुआ और वहां की अव्वाम ने शेख अब्दुल्ला को उनकी जगह से निकाल कर अपने भरोसे के दूसरे लोगों के हाथमें हुक्मत की बागडोर सौंपी। अमेरिका की यह तीसरी नाकामयाबी थी जो अशिया के अंदर उसने अपने पैर फैलाने के लिये की थी। आज कश्मीर का अंक बड़ा सवाल दुनिया के सामने है। कश्मीर में इस तरह से नाकामयाबी होने के बाद उन्होंने सोंचा कि किसी न किसी तरह से अशिया के अंदर हमारे फौजी अड्डे कायम होने चाहियें। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की अव्वाम में मजहबी जजबात का बहुत ज्यादा असर है। मैंने यह पहले ही बताया कि आज पाकिस्तान का मंशाशी ढांचा बुरी तरह से बिगड चुका है। अनाज मिलने वहां मुश्किल है, बेकारी बढ़ गयी है, मकानात का मसला अभी हल नहीं हुआ है। ऐसी हालत में पाकिस्तान की अव्वाम में मौजूदा हुक्मत के खिलाफ जबर्दस्त नाराजी

फैल रही थी और वहाँ की हुकूमत के लिये अंक जबर्दस्त खतरा पैदा हो गया था। उससे बचने के लिये पाकिस्तान की अक्वाम के मजहबी खियालात का फायदा उठाकर उसका ख्याल हुकूमत की तरफ से हटा कर किसी और चीज की तरफ दिलाने की कोशिश की गयी है, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ वह पूर्व पाकिस्तान में अभी अभी जो चुनाव हुआ, उनसे जाहिर होता है। मैं यह कह रहा था कि अमेरिका सोच रही थी कि किसी तरह से अशिया में फौजी अड्डे तैयार करने चाहिये, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से उसने फायदा उठाया। पाकिस्तान को अंक अड्डा बनाया गया और पाकिस्तान ने भी उसको कुबूल किया। इसके साथ साथ हमको अखबारात के जरिये से मालूम हुआ है कि टर्की (Turkey) और पाकिस्तान के बीच में भी मुआहदा हुआ है और अमेरिका और टर्की के बीच में अंक मुआहदा हुआ है। इस तरह से अमेरिका टर्की से लेकर पाकिस्तान तक अंक लाइन खींचना चाहता है जिससे अशिया के अंदर वह अपने फौजी अड्डे कायम कर सके और साम्राजियत को फैला सके। इसके बाद आपको मालूम है कि पाकिस्तान के वजीरे आजम ने अलान किया था कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच का मुआहदा अंक अंदरूनी मामला है, उसमें हिंदुस्तान या और किसी भी मुल्क को दखल देने का अख्तियार नहीं है। जिसमें कोअी शक नहीं कि यह पाकिस्तान का अंक अंदरूनी मसला है और पंडित जवाहरलालजी भी इसको मानते हैं, लेकिन अंक पडोसी मुल्क की हंसीयत से यह जरूरी हो जाता है कि उसके अंदरूनी मामले में जो अहम तबदीलियां हो रही हैं उसका असर हमारे ऊपर और दुनिया के ऊपर क्या होनेवाला है, क्योंकि आज के विज्ञान के अंदर बढी हुअी दुनिया बहुत छोटी हो गयी है। आपको मालूम होगा कि अंबोसीनिया पर जब अिटली ने हमला किया था तो वह मसला फौरन लीग ऑफ नेशन्स के सामने आया था। उसी तरह से जब जापान और मैनचूरिया के बीच में झगडा चल रहा था तो अंक पडोसी देश के नाते उस वकत हिंदुस्तान की अंग्रेजी हुकूमत ने बर्मा रोड को बंद किया और इसीलिये कि वहाँ की लडाअी यहाँ तक न आ जाय। आज के विज्ञान के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गयी है। अंक जगह कहीं कुछ हुआ तो उसके असरात सारी दुनिया पर होने लगें हैं। अंसी हालत में दुनिया आज जमहूरियत की तरफ जा रही है। जमहूरियत और अिन्सानियत के बीच गहरे ताल्लुकात ह। इसलिये जमहूरियत पर भरोसा रखनेवाले दुनिया के लोगों को सज्जग रहना पडता है कि अगर किसी मुल्क के अंदरूनी मामले का असर जमहूरियत पर बुरी तरह से होनेवाला है तो उसकी तरफ दुनिया का ख्याल खींचे, और अगर जमहूरियत पर तेज रफतार से कहीं हमला होने के अिमकानात मालूम हो रहे हों तो उनको रोकने की कोशिश करें, इसी लिहाज से आज हिंदुस्तान ने इस पाक-अमेरिका मुआहदे की मुखालिफत की है। जिसमें शक नहीं कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कोअी भी मुल्क अपने देश की आजादी के लिहाज से किसी दूसरे मुल्क के साथ मुआहदा करने के लिये आजाद होता है। लेकिन अशिया के बिरादरीन मुल्कों का यह फर्ज हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में अगर अिन्कलाबी तबदीली आ रही हो और उससे दूसरे मुल्कों को खतरा पैदा होता हो तो उसकी मुखालिफत करें क्योंकि यह कहा जाता है कि पडोसी मुल्क सब से पहला दुष्मन बन सकता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुअे हिंदुस्तान की हुकूमत ने यह जरूरी समझा कि पाकिस्तान के अंदर पैदा हुअी इस बैनूल अक्वामी तबदीलियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाय, अगर कोअी यह कहे कि शोंपडी के अंदर की बिजली को बंद करके मैं अपनी शोंपडी की हिफाजत करता चाहता हूँ तो वह अंक बहुत बडी मलती कर रहा है। शोंपडी के अंदर की बिजली बंद करने

के माने झोंपड़ी की हिफाजत करना नहीं है बल्कि उसको जलाकर खाक करने की तदाबीर अख्तियार करना है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच का यह मुआहदा अच्छे ख्यालात से बनाया गया होता तो उसकी मुखालिफत करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन असली बात अलग है। इसीलिये हिंदुस्तान के वजीरे आजम ने जो आज अशिया के अमन का पैगम्बर है, दुनियाकी अिन्सानियत जो आज तबाही की तरफ जा रही है उसको बचानेकी जो कोशिश कर रहा है, उसने अशियाके लोगोंको तबाही से बचनेके लिये यह आवाज उठायी है। उसका मनशा यह नहीं है कि पाकिस्तान की अक्वाम के साथ अच्छे जजबात पैदा न किये जायें, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो आंतरराष्ट्रीय हालात पैदा हो गये हैं, उनके बारे में पाकिस्तान की अक्वामको जागृत करने के लिये हिंदुस्तान अपना अेक सही फर्ज अदा कर रहा है, और इस फर्ज को अदा करनेके लिये ही हिंदुस्तान की हुकुमत ने हिंदुस्तानकी असेंबलियों के जरियेसे इस सवाल को अक्वामके सामने रखा है। मुझे खुशी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पालिसी के खिलाफ इस मुआहदे के होने से दो घंटे पहले तक सियासी जमातों की तरफसे हिंदुस्तान में बहुत मुखालिफत होती रही। लोग कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू की सियासी पालिसी बहुत खराब है, दुनिया के दूसरे मुमालिक से अलग रहकर आज की दुनिया के पालिटिक्स में हम अपनी आजादी को कैसे कायम रख सकते हैं। अभी अभी अेक ऑनरेबल मेंबर ने यह कहा कि हिंदुस्तानके अंदर फौजी ट्रेनिंग का अिन्तजाम किया जाना चाहिये। मैं कहूंगा कि दुनिया का कोयी भी मुल्क अपनी फौजी ताकत को बढाकर अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकता। हमने देखा है कि ८० करोड डालर का सामान चीन को दिया गया लेकिन नेशनलिस्ट सरकार वहां न अपने को कायम रख सकी न अमेरिका अपना अिरादा पूरा कर सका बल्कि अमेरिका ने खुद अपने हाथोंसे वहां अपनी कबर खुदवाली। आज पाकिस्तान को भी इसी तरहकी अिमदाद दी जा रही है लेकिन उसका नतीजा वही होनेवाला है जो हमने चायना में देखा। इसलिये हमको किसी से हथियार की अिमदाद नहीं लेना है। आपको मालूम होगा कि अभी अभी कलकत्ते के चेंबर आफ कामर्स की मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स और दीगर स्कीम्सके बारे में कहा कि इसके बाद अगर हमको अमेरिकासे या दूसरे किसी मुल्कसे अिमदाद न मिले तोभी हमें उसकी परवाह नहीं, चाहे हमारे तरक्की रुक जाय लेकिन इस तरह की अिमदाद लेकर अमेरिकाके जजबात को हिंदुस्तान में बढने का मौका हम नहीं देंगे और अपनी आजादी को साम्राजियतके हाथ बेचना कभी पसंद नहीं करेंगे। इसलिये आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातें इस मौके पर मुत्तफिक हो गयी हैं। इसलिये इसी मौके पर अपोजीशन पार्टी के मेंबरों पर मैं सही तौर पर यह वाजे करना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच इससे मुत्तफिक हैं और आप समझते हैं कि मुल्क अेक संकट की प्ररिस्थिति से गुजर रहा है तो आपके वह रोजमर्रा के हडताल, वह शोरगुल वह नारेबाजी अेकदम खतम कर दीजिये और वह उस वक्त तक खतम कर दीजिये जिस वक्त तक हम यह न समझें कि हमारा मुल्क अब खतरे से बाहर हो गया है। उसके बाद फिर हम अपने अपने ख्याला त को लेकर मैदान में आयेंगे और अपना अपना काम करते रहेंगे यही मौका है जब कि हमअेक होकर अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं। मुझे अम्मीद है कि हिंदुस्तान के लोग ही नहीं बल्कि पूरे दुनियाके लोग इस पाक-अमेरिका मुआहदे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे और मुझे यह भी अम्मीद है कि पाकिस्तान का यह मुआहदा इसी तरह से खतम होगा जिस तरह से चीन और अमेरिका का मुआहदा खतम हुआ और जिस तरह से चीन में अमेरिका ने

अपनी कबर खुदवा ली अुसी तरह से अेक दिन पाकिस्तान में भी वह भी अपनी कबर खुदवा लेगा ।
अिन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खतम करता हूँ ।

Shri V. B. Raju : Mr. Speaker, Sir, The purpose of this resolution is not to make.....

شری داجی شنکر (عادل آباد) - یہ بہت اہم رزلوشن ہے اس لئے یا تو تلگو میں
بولنے کی اجازت دی جائے یا اردو میں بولیں۔ تلگو میں بھی کہیں تو ایوان کے بہت سے
لوگ سمجھ سکتے ہیں -

مسٹر سپرمن :- میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کی انٹرنیشنل اہمیت کے لحاظ سے
انگریزی میں تقریر کرنا اچھا ہوگا۔

شری داجی شنکر - اردو میں بولنے پر بھی سمجھ سکتے ہیں -

Shri V. B. Raju : Our purpose is not to make any particular nation target of our discussion and create prejudice. We are not discussing on this resolution with a view to make either America or Pakistan the target ; but by raising our voice we want to dissuade the Governments of those two countries from doing, what we consider, a wrong thing.

The modern state, as it is constituted, is becoming centralised in its structure and dictatorial in its outlook. It has become very undependable and as such we want to appeal to the democratic elements both in America and Pakistan to compel their Governments to withdraw from the proposed pact or alliance, and, on the other hand, to see that the World Governments would sit around a table and find out a way to prevent any war taking place in the world. That, as I understand, is the main purpose of our resolution.

From this House, I would like to point out to the Peoples of America,—if our message could reach them or if this cry should reach them—that for more than hundred years they have actually adopted the same policy as Pandit Nehru has been adopting during these seven years. It has been said by their respected Ex-Presidents and by the President too that they do not like to entangle themselves into unnecessary cliques or into world confusion. The famous Jefferson, on his assumption of the Presidentship, had said : “Friendship with all nations and entangling alliances with none”. Similarly, President Washington had declared “Europe as a set of primary interests which to us have a very remote interest. It must be unwise to ask to implicate ourselves”. Today, Our Pandit Nehru too is saying the same thing :

“Friendship with all nations of the world and no joining with any entangling cliques”. Pandit Nehru’s approach is gradually being realised by certain elements in America. The Ex-Administrator of Marshal Plan Administration has said, in connection with the transaction of giving wheat to India wherein the Americans wanted some sort of returns out of that bargain, that only immature Americans would like to make Indian school-children salute the U.S. Flag each day as the price of the wheat to India. Mr. Paul Haffman reiterated the same when he said: “By giving Indians wheat, you cannot expect the Indian Children salute the American Flag. If you want to purchase it like that, you are in a Fool’s Paradise”. This is not an Indian’s saying; it is an American himself saying this. The present President has said that America should be understood from its history, not from stray pages from History. I would like the President himself to read the American history and know what better America can do in the context than India as placed today. That is all what I would like to appeal to the Americans from the floor of this House.

Indians feel today, and the public opinion as represented by Pandit Nehru is, that India, particularly the Asiatic nations, should not be involved in a war. The anxiety of America, as it appears to us, is to shift the war theatre from Europe to Asia. I have gone through certain books of eminent people wherein it has been recorded that America wants to fight Russia on the Asian soil; that America would prefer to throw the atom bomb on Peiking then on Moscow; and that America is interested in racialism as a home problem. When big people say about America in those terms, we begin to suspect the approach that America has taken towards Pakistan.

I would ask, what does Pakistan gain by entangling itself in the international confusion? Why is it that Pakistan is cutting adrift from the Asian-African Block? Why is it that America is trying to break the Arab-League by forming associations with Turkey, Iraq and Pakistan? What necessity has arisen today for Pakistan to go away from the main current? Certainly I feel and I am even afraid that the people of Pakistan are not fully informed of all these developments; I am further afraid that because of certain unemployment situation in Pakistan and also because of the economic unstability in Pakistan people are

simply made to believe that there are certain elements in India which are not sure of Pakistan's existence. I would like to appeal to the people of Pakistan and impress upon them that we in India,—all the three main political parties in India—believe that Pakistan is a reality. If Pakistan wants to join India in a federal way, it is for Pakistan to voluntarily do it and India, on its own accord, will never think of compelling Pakistan to join India. Pakistan is a making of India with her own hands, whether we liked it or not. Situated as we then were, we had to do it and it was history that compelled us to do it. The three important events that happened after world war II were the division of three countries; Germany, Korea and India. While there was voluntary division in India, Germany and Korea have been divided against the wishes of the people and that is the reason why those countries are going to be new causes for another World War. The results that emerged from the second World War have again become causes for a Third World War. But it shall not be the case with regard to India. Pakistan is the area which we have created: it is not because of America saying so or Russia asking us. We have created Pakistan with our own hands and the people of Pakistan should be convinced of our *bona fides*. We do not want to compel Pakistan to join us. Pakistan has itself got an economic interest by associating with India, particularly in regard to natural resources and canal waters. Canal waters is a very important problem—More than tanks, jeeps and other equipment, water and wheat are important to Pakistan. Pakistan people are not being educated on these lines. It is a pity.

I will now go a step further and say that mere platitudes or mere appeals or mere shedding of tears are not in themselves going to deter America in its plan for aggression. America is not interested in India; it is not interested in Pakistan: America is interested more in filling a particular vaccum. When we turn the pages of our History we find that in Asia there were three empires: the British the Dutch and the French. The Britishers by leaving India and Pakistan have created a vaccum and the British losing its hold in the middle-east have created a vaccum. The Dutch has left Indonesia and the French in spite of 55 per cent of more of war expenses being met by America has not been able to make any headway in Indo-China. That being the case, America wants to assume the role or fill the gap by itself. It is to be taken as

a practical reality. America does not like Asia uniting or the resurgent nationalism in Asiatics. The fundamental tussle is between the industrial powers of the world and the powers of backward economy. The industrial powers of Europe had kept America; kept Asia; kept Africa and Australia, under their grip and had prospered so much that America itself had to struggle to come out of the grip of the European powers. What America did earlier, Asia is doing now. Let America recall its own history. Peoples of America had struggled to get out of the grip of the industrial powers: Asiatics are doing the same thing. From Turkey to Japan all the countries in Asia, all the nations of Asia, are struggling to come out of the grip of the European industrial powers. In this process, America is not helping us. America is placing before us a bogey of communism. Whether communism or no communism, whether capitalism or super-capitalism, one thing is certain that no one Nation today can exploit other nations. - We have to believe that national integrity is the only real way of keeping peace in the world. How these nations have been created artificially is not a point for consideration now, but we accept certain geographical boundaries or certain Governments as realities and accept their integrity and Sovereignty. As long as Soviet Russia and America do not respect this national integrity, both will be hated by the peoples of the world. We differ from Soviet also on this point. They also uphold the theory of "peace through strength." Let us not take sides when we argue here. We are Indians first. The signs of a cold war are coming nearer to the boundaries of India. We should speak as Indians with higher objectives that war should be averted once and for all. If we take sides with Soviet or America in this House and begin to argue, we do not have a true picture.

Scientific technology is being applied to war. Whether it is rightly applied or wrongly applied, the fact is— it is being applied. Soviet, America and some others want to take advantage by applying this scientific technology to war and they say "Peace Through Strength", whereas we say "Peace through Understanding." It is through collaboration. Misunderstanding or wrong understanding creates suspicion; suspicion creates fear; fear compels to armaments; armament takes to military action; military action or war brings degeneration. That is how the process takes place. Therefore, I wish there should be proper understanding between the different nations of the world and let there be

“Peace Through Understanding.” The fundamentals of Pandit Nehru’s policy are no entanglements in any cliques of the world and friendship with all nations. But why did America differ with India on this point? America also says that there should be peace; it also says there should be no entanglements in cliques. But then what is her present policy due to? We have to go to the root cause. Firstly, America did not like India speaking in favour of New China. America never expected that Pandit Nehru would be such an independent and firm personality who could call a spade a spade. Indias, speaking in favour of China for its inclusion in the United Nations Organization has not been very happy to America. The second thing is that India did not like that Macarthur should be given power to enter into North Korea. Thirdly, India did not like signing the Japanese peace treaty as per the draft prepared by America. On these three points, America has become dissatisfied.

We must now go to the root cause and find out what America wants us to do. I think America and India has both misunderstood each other. Without taking much time of the House, in a minute or two I say about a parable in this connection. One person had been to the philosopher Voltaire and said to him: “So and so is a good philosopher.” Immediately, Voltaire said ‘Yes, I know he is a fine man, a big man.’ But that person thereupon said: “But when I said to him that you are a good man, he called you a bad man. But how is it you call him a good man.” Then Voltaire said: “We might have both misunderstood each other.” I do not know if I am clear about the subtlety here. What Voltaire said was that the other person must be a scoundrel and ‘I must be a gentleman.’ That is how we might have misunderstood each other. America seems to have thought that India in its predicament or in the context of her present economic poverty will surrender its wider interests. We too might have misunderstood that America has good intentions to uphold our Democracy. Otherwise, 7 years of friendship would not have ended like this. I am glad at least today we have understood each other. Though India does not want leadership of the Asian-African countries, the small nations in Asia and Africa do look to India for succour. America obviously does not like this and it is to remove India from this position that America is trying to set up Pakistan against India. Certainly, America is doing the greatest disservice to the freedom of ours. We do not want any nation to come and fall on our shoulders. We fought for Indonesia; We raised our voice for

Africa, Tunisia and South Korea and North Korea ; wherever there was aggression we raised our voice. If America wants to belittle India or bring down India or coerce India, it is going to do a great mistake.

Lastly, I would say, let us not mix our home politics with the foreign politics. We will be committing a great mistake if we associate our home politics with foreign affairs. Let us see England and learn : whatever be their Home differences, in foreign policy matters, all the political parties come together. That is British Democracy. There is nothing wrong in copying some good elements of the British democracy. Therefore, let us see that we do not mix our home politics with foreign affairs and let us all follow one leader in facing this crisis. It is a great crisis and should our apprehensions come true, it is going to be the greatest disaster to the world.

শ্রী. জে. অনন্দরাম, (সি.সি.ল্যা.--জনরত্ন)

স্পীকার, সর্,

গৌরব সభ్యল চা'লমন্দি ఈ తీర్మానంపై ఉపస్థనించారు. ఈ తీర్మానం మనందరి సమిసి పరియోజనాలకు సంబంధించినది కాబట్టి దీనిలో ఎలాంటి భేదాలు లేకుండా ఉండాలని తీర్మానం పరిపాదించివారియుక్త ఉద్దేశం

مسٹر چیرمن - آپ ہندی میں تقریر کریں -

شری جے۔ آند راؤ۔ مسٹر اسپیکر سر۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ریزولوشن یہاں لایا گیا اور اس پر بہت سے لوگوں نے اپنے متفقہ خیالات ظاہر کئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند سمبروں نے جو ریزولوشنس کئے ہیں ان پر دکھ بھی ہوتا ہے۔ اس قسم کے ریزولوشنس رکھنے سے کہ آئندہ فلاں قوتیں جارحانہ اقدامات کرنے والی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ریزولوشنس کرتے وقت اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے اس چیز کو کنسیدر (Consider) نہیں کیا کہ اندرونی اختلافات ہوسکتے ہیں۔ دیش کی بھلائی کے لئے مختلف نظریات ہوسکتے ہیں۔ ملک کی خوشحالی کے متعلق نظریات میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ معاشی خوشحالی کے جو تصورات اور جو بیچارہ رکھتے ہیں اس میں اختلافات ہوسکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم بھی پیٹریاٹ (Patriot) ہیں ہم بھی محب وطن ہیں۔ اختلافات کے باوجود جب کوئی اگریشن (Aggression) ہم پر ہو تو سب کے سب ایک ہو کر اس کا مقابلہ کرسکتے ہیں۔ ٹریڈری بنچس کے ایک آئریبل سمبر نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ برٹش ڈیموکریسی کی یہ شاندار روایات ہیں کہ جب بدیشی حملہ آور

“Peace Through Understanding.” The fundamentals of Pandit Nehru’s policy are no entanglements in any cliques of the world and friendship with all nations. But why did America differ with India on this point? America also says that there should be peace; it also says there should be no entanglements in cliques. But then what is her present policy due to? We have to go to the root cause. Firstly, America did not like India speaking in favour of New China. America never expected that Pandit Nehru would be such an independent and firm personality who could call a spade a spade. Indias, speaking in favour of China for its inclusion in the United Nations Organization has not been very happy to America. The second thing is that India did not like that Macarthur should be given power to enter into North Korea. Thirdly, India did not like signing the Japanese peace treaty as per the draft prepared by America. On these three points, America has become dissatisfied.

We must now go to the root cause and find out what America wants us to do. I think America and India has both misunderstood each other. Without taking much time of the House, in a minute or two I say about a parable in this connection. One person had been to the philosopher Voltaire and said to him: “So and so is a good philosopher.” Immediately, Voltaire said ‘Yes, I know he is a fine man, a big man.’ But that person thereupon said: “But when I said to him that you are a good man, he called you a bad man. But how is it you call him a good man.” Then Voltaire said: “We might have both misunderstood each other.” I do not know if I am clear about the subtlety here. What Voltaire said was that the other person must be a scoundrel and ‘I must be a gentleman.’ That is how we might have misunderstood each other. America seems to have thought that India in its predicament or in the context of her present economic poverty will surrender its wider interests. We too might have misunderstood that America has good intentions to uphold our Democracy. Otherwise, 7 years of friendship would not have ended like this. I am glad at least today we have understood each other. Though India does not want leadership of the Asian-African countries, the small nations in Asia and Africa do look to India for succour. America obviously does not like this and it is to remove India from this position that America is trying to set up Pakistan against India. Certainly, America is doing the greatest disservice to the freedom of ours. We do not want any nation to come and fall on our shoulders. We fought for Indonesia; We raised our voice for

Africa, Tunisia and South Korea and North Korea ; wherever there was aggression we raised our voice. If America wants to belittle India or bring down India or coerce India, it is going to do a great mistake.

Lastly, I would say, let us not mix our home politics with the foreign politics. We will be committing a great mistake if we associate our home politics with foreign affairs. Let us see England and learn : whatever be their Home differences, in foreign policy matters, all the political parties come together. That is British Democracy. There is nothing wrong in copying some good elements of the British democracy. Therefore, let us see that we do not mix our home politics with foreign affairs and let us all follow one leader in facing this crisis. It is a great crisis and should our apprehensions come true, it is going to be the greatest disaster to the world.

శ్రీ జె. అనందరావు, (సిర్సిత్లా--జనరల్)

స్పీకర్, సర్,

గౌరవ సభ్యులు చాలమంది ఈ తీర్మానంపై ఉపస్థితులారు. ఈ తీర్మానం మనందరి సమిష్టి పరియోజనాలకు సంబంధించినది కాబట్టి దీనిలో ఎలాంటి భేదాలు లేకుండా ఉండాలని తీర్మానం ఘోషించివారియుక్త ఉద్దేశం

مسٹر چیمرمن - آپ ہندی میں تقریر کریں -

شری جے۔ آندراؤ۔ مسٹر اسپیکر سر۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ریزولوشن یہاں لایا گیا اور اس پر بہت سے لوگوں نے اپنے متفقہ خیالات ظاہر کئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ممبروں نے جو ریزولوشنس کئے ہیں ان پر دیکھ بھی ہوتا ہے۔ اس قسم کے ریزولوشنس رکھنے سے کہ آئندہ فلاں قوتیں جارحانہ اقدامات کرنے والی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ریزولوشنس کرتے وقت اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے اس چیز کو کنسیدر (Consider) نہیں کیا کہ اندرونی اختلافات ہوسکتے ہیں۔ دیش کی بھلائی کے لئے مختلف نظریات ہوسکتے ہیں۔ ملک کی خوشحالی کے متعلق نظریات میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ معاشی خوشحالی کے جو تصورات اور جو میعار ہم رکھتے ہیں اس میں اختلافات ہوسکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم بھی پیٹریاٹ (Patriot) ہیں ہم بھی محب وطن ہیں۔ اختلافات کے باوجود جب کوئی اگریشن (Aggression) ہم پر ہو تو سب کے سب ایک ہو کر اس کا مقابلہ کرسکتے ہیں۔ ٹریڈری پنچن کے ایک آئریبل ممبر نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ برٹش ڈیموکریسی کی یہ شاندار روایات ہیں کہ جب بدیشی حملہ آور

آتے ہیں تو اختلافات کے باوجود تمام پارٹیاں ایک ہو جاتی ہیں۔ جب ہم وہاں کی پارلیمنٹ کے نمونے اختیار کر رہے ہیں تو اس سلسلہ میں بھی اختیار کرنا چاہیئے۔ جو اعلیٰ قسم کی ڈیموکریسی کی مثال انہوں نے دی ہے اس کے لئے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس قسم کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی جذبہ سے ہم کام کریں تو ہماری جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے۔ ہم ایکٹا کے ساتھ ایسے دیشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ فرقہ پرستی کی آڑ لیکر ملک کو غلام بنانا چاہتے ان کو کبھی اس کا موقع نہیں دینا چاہیئے۔

امریکہ کی جو پالیسی حال میں ظاہر ہوئی وہ کوئی انسیدینٹل (Incidental) یا اتفاق نہیں ہے۔ بلکہ اس کے پیچھے پوری دنیا کو غلام بنانے کا منصوبہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ جیسا کہ ایک آنریبل ممبر نے کہا سوویت روس اور چائینا پر حملہ کر کے اون کو ختم کرنا ہے۔ میں اون دیشوں کی وکالت کرنے کے لئے نہیں کھڑا ہوا ہوں۔ آج دنیا میں دو گروپس بن گئے ہیں ایک سامراجی اور دوسرے سوشلسٹ۔ امریکہ جو سامراجی گروپ سے تعلق رکھتا ہے وہ اس انداز سے دیکھ رہا ہے کہ دوسروں کو غلام بنا کر اونکی معاشی مدد کر کے اون کو لوٹا جائے۔ لیکن اس میں ناکام ہو رہا ہے۔ آج اوس کو اپنا مال کھپت کرنے کے لئے مارکٹ کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جو دائرہ اوس کے مال کی کھپت کے لئے تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ چائینا ایک بہت بڑا ملک ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اسی طرح سے سویت ریشیا اور دیگر مشرقی ممالک میں اوس کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اس وجہ سے وہ ہندوستان اور پاکستان میں اٹے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اون کو معاشی مدد دیکر۔ اونکی خوشی حالی کی باتیں کر کے۔ وہاں کی انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنے کے نام پر میٹھی میٹھی باتیں کر کے اون کو ہمیشہ کے لئے کچل کر رکھ دینا چاہتا ہے۔ کوریا کی جنگ ختم ہونے کے بعد اوس کے جنگی ساز و سامان کے کھپت کیلئے کوئی مارکٹ نہیں مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج امریکہ جیسے سرمایہ دار ملکوں میں بھی یروزگاری کا مسئلہ شروع ہو گیا ان امپلائمنٹ کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ بیروزگار بنتے جا رہے ہیں۔ اس لئے اپنے کارخانوں کو چالو رکھنے کے لئے اپنے مال کی کھپت کرنے کے لئے اپنے ملک کی اکنامک کرائسس (Economic crisis) کو دور کرنے کے لئے وہ مجبور ہے کہ کسی نہ کسی طرح دوسرے ملکوں میں مستقل طرز پر اپنا سکھ بٹھائے۔ اس پر ہمیں خاص طور پر غور کرنا چاہیئے۔ آنریبل موور آف دی ریزولوشن نے اکنامک ریلیشنس کے تعلق سے ایک سینٹنس جو پہلے رکھا گیا تھا بعد میں نے اوس کو وٹھ ڈرا کر لیا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اوس کو ویسا ہی رکھنا چاہئے تھا۔ لیکن اون کا منشا یہ ہوگا کہ اکنامک تعلق رکھنے پر بھی یہ نتیجہ نکلیگا امریکہ ہم کو غلام بنالیاگا۔ کمیونٹی پراجکٹ کے نام پر انڈسٹریز کے نام پر جو پیسے دئے جا رہے ہیں اوس کے نتیجے کے طور پر کمیونٹی پراجکٹ ڈولپمنٹ کے نام پر امریکہ کے اسپائز (Spies) اور

ایجنٹ یہاں آجائینگے اور تعلیم یافتہ طبقہ میں پرچار کرینگے۔ انٹسٹریز کو ڈولپمنٹ کرنے کے بہانے۔ پیداوار میں اضافہ کرنے کے بہانے وہ یہاں گھس آئینگے۔ اور اون حملہ آوروں کو موقع ملیگا کہ یہاں کے بہت سے لوگوں کو اپنے ایجنٹ کے طور پر استعمال کریں۔ جس طرح کہ ماضی میں سامراج یہاں آیا تھا اوسی طرح اب بھی آنا چاہتا ہے۔ اس سے ہم کو آگاہ ہو جانا چاہئے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی دو سو سال قبل ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم دو سو سال کی غلامی کے بعد آزادی کی جنگ لڑ کر آزادی حاصل کئے ہیں اوس زمانے میں جب برٹش آئے تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا کہ ہم تجارت کیلئے آئے ہیں۔ وہ لوگ اوس وقت تاجروں کے بھیس میں آئے تھے اوس وقت بھی ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو کہ یہ لوگ حکومت کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں۔ ہمارے سامنے پچھلی ہسٹری موجود ہے کہ کس طرح ہوتے ہوئے یہ تاجر حکمران طبقہ بن گئے۔ اسی طرح سے آج جو امریکن ایڈ (American aid) دیا جا رہی ہے اور جو ملٹری اکسپرٹس آرہے ہیں اونکے پیچھے سامراجی مقصد مضمر ہے۔ لیکن آج یہ مقصد کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ آج ہمارے عوام بیدار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے لڑائی لڑ کر آزادی حاصل کی ہے۔ امریکی سامراج یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری آزادی کو لے لیگا لیکن ایک الگ طریقہ سے وہ یہاں آنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اکنامک امداد کی وجہ سے اسکو کئی گونا گوں سہولتیں حاصل رہینگی۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی ڈھنگ سے یہاں آجائیکا۔ رپورٹ میں جن اکنامک رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے اوسمیں زہر چھپا ہوا ہے۔ ہم کو اس سے آگاہ ہو جانا چاہئے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے یہ تمام باتیں ہونے والی ہیں۔

مسٹر چیئرمین۔ ہم اب اڈجورن ہوتے ہیں۔ پیر کے دن ۲۔۳ پر پھر ملیں گے۔

The House then adjourned till Half Past Two of the Clock on Monday, the 22nd March 1954.

